



वर्ष-31 अंक : 147 (हैदराबाद, निजामाबाद, विशाखापट्टणम, तिरुपति से प्रकाशित) श्रावण शु.14 2083 गुरूवार, 27 अगस्त-2026

THE LARGEST CIRCULATED AND READ HINDI DAILY IN TELANGANA & ANDHRA PRADESH



epaper.vaartha.com

Vaartha Hindi

@Vaartha_Hindi

Vaartha official

www.hindi.vaartha.com

‘अरावली’ से आसमान में बढ़ेगी ताकत- भारत-फ्रांस बनाएंगे ताकतवर इंजन

नई दिल्ली, 26 अगस्त (एजेंसियां)। भारत और फ्रांस मिलकर नई पीढ़ी का शक्तिशाली हेलीकॉप्टर इंजन बनाएंगे। इस इंजन का नाम ‘अरावली’ रखा गया है। यह 3,500 से 4,000 एसएचपी शक्ति वर्ग का होगा। इस इंजन का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसके लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और फ्रांस की सैफरान हेलीकॉप्टर इंजन ने अंतिम अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों कंपनियों की संयुक्त कंपनी सफहल (एसएएफएचएएल) हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ है।

प्रधान संपादक - डॉ. गिरीश कुमार संधी हैदराबाद नगर ॐ पृष्ठ : 16 मूल्य : 8 रुपये

'समाज में दया और सद्भाव की भावना मजबूत होगी'

पीएम मोदी ने दी ईद और ओणम की शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 26 अगस्त (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद-ए-मिलाद-उन-नबी और ओणम के अवसर पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ईद मुबारक। इसके साथ ही अन्य कई नेताओं ने भी बधाई दी है।



पीएम मोदी की ओर से एक्स पोस्ट में लिखा गया, 'मिलाद-उन-नबी की बधाई। मुझे उम्मीद है कि यह अवसर हमारे आस-पास एकता और खुशियां बढ़ाएगा। दया और समाज के प्रति योगदान की भावना हमेशा हमारा मार्गदर्शन करे।' रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मिलाद-उन-नबी की बधाई। यह अवसर सभी के लिए शांति और समृद्धि लाए। मुझे उम्मीद है कि हमारे समाज में आपसी सद्भाव और दया की भावना और मजबूत होगी। ईद मुबारक।' केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, 'ईद मिलाद-उन-नबी की हार्दिक बधाई! यह पर्व आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। शुभकामनाएं।' केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'ईद मुबारक! मिलाद-उन-नबी के पवित्र अवसर पर सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व हमारे समाज में एकता, सौहार्द और खुशहाली को और मजबूत करे। करुणा, दया और समाज के वंचितों के प्रति सेवा का भाव हमेशा हम सभी का मार्गदर्शन करे।'

पीएम मोदी ने बालेन शाह से की बात

नई दिल्ली, 26 अगस्त (एजेंसियां)। नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने बाढ़ के कारण हुई मौतों पर शोक जताया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल को हर संभव मानवीय और राहत सहायता देने का भरोसा दिया। नेपाल में बाढ़ के कारण कई इलाकों में हालात गंभीर बने हुए हैं। भारत ने संकट की इस घड़ी में नेपाल के साथ खड़े रहने और जरूरत के मुताबिक राहत एवं मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है।

लिखा, 'मिलाद-उन-नबी की बधाई। यह अवसर सभी के लिए शांति और समृद्धि लाए। मुझे उम्मीद है कि हमारे समाज में आपसी सद्भाव और दया की भावना और मजबूत होगी। ईद मुबारक।' केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, 'ईद मिलाद-उन-नबी की हार्दिक बधाई! यह पर्व आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। शुभकामनाएं।' केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'ईद मुबारक! मिलाद-उन-नबी के पवित्र अवसर पर सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व हमारे समाज में एकता, सौहार्द और खुशहाली को और मजबूत करे। करुणा, दया और समाज के वंचितों के प्रति सेवा का भाव हमेशा हम सभी का मार्गदर्शन करे।'

शिवकुमार बोले-कर्नाटक में वंदेमातरम के 2 पैरे ही गाए जाएंगे

बेंगलुरु, 26 अगस्त (एजेंसियां)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य में वंदे मातरम के सिर्फ दो छंद (पैरे) ही गाए जाएंगे। मैं पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता हूं और हम इस फैसले पर कायम रहेंगे। भाजपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। शिवकुमार बेंगलुरु में इंडिया टुडे के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने कहा- स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम उनकी जानकारी के बिना गाया गया था, लेकिन भविष्य में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में अब राष्ट्रगीत के दो ही छंद गाए जाएंगे।

दरअसल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी ने 19 अगस्त को ऐलान किया था कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ शुरुआती दो पैरा ही गाएगी। यह फैसला 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गान को लेकर हुए विवाद के बाद आया। भाजपा ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट : राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पद से हटाने की मांग

*** जज ने सीजेआई को लिखा पत्र**



नई दिल्ली, 26 अगस्त (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सदीप मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत से आग्रह किया है कि वे राजस्थान हाईकोर्ट के प्रमुख के तौर पर किसी दूसरे हाईकोर्ट से एक नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करें। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पर कई आरोप भी लगाए हैं।

एक प्रमुख विधि पोर्टल 'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस मेहता ने 2, 10 और 17 अगस्त को लिखे तीन पत्रों में जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को तुरंत हटाने की मांग की। उन पर प्रशासनिक शक्तियों के कथित दुरुपयोग, मामलों की सूची तैयार

करने में हेरफेर और कुछ वकीलों व पक्षों के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाया गया।

राजस्थान हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होकर पहुंचे जस्टिस मेहता ने कथित तौर पर कई बार सीजेआई से किसी दूसरे राज्य से नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मंजूरी मांगी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा न करना 'स्थान के हित के पूरी तरह खिलाफ' है। जस्टिस मेहता ने एक पत्र में कहा, 'मैं आपसे बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट के लिए किसी दूसरे राज्य से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का फैसला लें, ताकि इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को रोका जा सके। मेरी राय में, इस अनुरोध को लागूतार नजरअंदाज करना संस्थान के हित के पूरी तरह खिलाफ है।'

2 अगस्त के अपने पत्र में जस्टिस मेहता ने राजस्थान के अपने दौरो का जिक्र किया और दावा किया कि राजस्थान हाईकोर्ट के कई जजों ने उनसे मुलाकात की और जस्टिस शर्मा के कथित व्यवहार पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि जस्टिस शर्मा अक्सर अपने साथी जजों को बदले की कार्रवाई, जैसे स्थानांतरण की धमकी देते हैं। जस्टिस मेहता ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के न्यायिक और प्रशासनिक कामकाज के तरीके की भी आलोचना की।

स्नातकों के बीच बेरोजगारी दर अधिक

केवल 8.25% स्नातक ही अपनी योग्यता के अनुसार कर रहे काम

नई दिल्ली, 26 अगस्त (एजेंसियां)। रोजगार और परीक्षा की समस्याओं को लेकर आए दिन हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच नीति आयोग ने कहा है कि स्नातकों के बीच बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। बीए, बीएससी और बीकॉम जैसी सामान्य डिग्रियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता भी इस समस्या को बढ़ा रही है, क्योंकि इन डिग्रियों से सीधे रोजगार मिलने की संभावना कम होती है।

आयोग ने शनिवार को जारी अपनी रिपोर्ट 'गैडमैजनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत' में यह भी रेखांकित किया है कि भारत में 90% से अधिक स्नातक ऐसे काम कर रहे हैं, जो उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं हैं। थिंक टैंक का कहना है कि ग्रीन इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में रोजगार से जुड़े विशेष पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की जरूरत है।

संयुक्त राष्ट्र पैनल का बयान बेहद दुर्भावनापूर्ण

भारत ने सुनाई खरी-खरी, बोला-हमारे सॉलिसिटर जनरल ने पहले ही खारिज कर दिया था

नई दिल्ली, 26 अगस्त (एजेंसियां)। भारत ने बुधवार यानी 26 अगस्त, 2026 को संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र की 'नस्लीय भेदभाव खत्म करने वाली समिति (सीईआरडी)' की देश के बारे में की गई टिप्पणियों को सिर से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूएन पैनल के बयान को 'राजनीति से प्रेरित' और 'बेहद दुर्भावनापूर्ण' बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक

आधिकारिक बयान में कहा कि उसने 11-12 अगस्त को जिनेवा में आईसीईआरडी के तहत भारत की 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद समिति द्वारा जारी टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया एक सामान्य संधि-निकाय समीक्षा थी, जिसमें भारत ने रचनात्मक जुड़ाव की भावना के साथ भाग



लिया था। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि नस्लीय भेदभाव से निपटने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दृढ़ और अटूट है। भारत रिपोर्ट में शामिल

किसी भी राजनीतिक रूप से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण संदर्भ को पूरी तरह से खारिज करता है और इसकी कड़ी निंदा करता है। समीक्षा प्रक्रिया के दौरान भारत ने अपने संवैधानिक सुरक्षा उपायों,

परीक्षा से दो दिन पहले पहुंचा पेपर

एमपीएससी ने रद्द की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती, एफआईआर पर घिरी महाराष्ट्र सरकार

मुंबई, 26 अगस्त (एजेंसियां)। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में ड्रा इंस्पेक्टर, ग्रुप-B पद की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। यह फैसला 22 मार्च की स्क्रീनिंग परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर लिया गया। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि परीक्षा से दो दिन पहले ही कुछ अभ्यर्थियों के पास प्रश्नपत्र या उसके सवाल पहुंच गए थे।

मनसे नेता सदीप देशपांडे ने सरकार से एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए पूछा है कि अगर शुरुआती जांच में पेपर लीक की बात सामने आई है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और आखिर किसे बचाया जा रहा है। आयोग को कुछ अभ्यर्थियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से ईमेल के जरिए परीक्षा में कथित अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं।

डीआरडीओ के स्वदेशी पैराशूट ने रचा इतिहास

जहां सांस लेना भी चुनौती, वहां सफल रहा स्वदेशी एमसीपीएस का परीक्षण

नई दिल्ली, 26 अगस्त (एजेंसियां)। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों की पैराशूट क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की आगरा स्थित एडीआरडीई द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (एमसीपीएस) का दुनिया के सबसे ऊंचे ड्राप जॉन में शामिल न्योमा के मुघ ड्राप जॉन में सफल परीक्षण किया गया।

22,000 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग इस परीक्षण के दौरान एडीआरडीई के प्रशिक्षित परीक्षण जम्परों ने करीब 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। यही नहीं, इस ऊंचाई पर तापमान करीब माइनस 15 डिग्री सेल्सियस था। इतनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद पैराशूट प्रणाली और उससे जुड़े सभी स्वदेशी उप-तंत्रों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। परीक्षण के दौरान एडीआरडीई के मुख्य परीक्षण जम्पर विंग कमांडर राहुल झा, एमडब्ल्यूओ आर. जे. सिंह, वीएम (जी) और एमडब्ल्यूओ विवेक तिवारी ने 22,000 फीट की ऊंचाई से यह छलांग लगाई।



इस परीक्षण की खास बात यह रही कि यहां केवल पैराशूट ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया। इनमें स्वदेशी पैरा कंप्यूटर, ऑक्सीजन प्रणाली और विशेष जंपसूट भी शामिल थे। यह पूरा तंत्र अत्यधिक ऊंचाई पर भी भरोसेमंद साबित हुआ है। परीक्षण ने यह साबित किया कि एमसीपीएस बेहद कम तापमान और अत्यधिक ऊंचाई जैसी कठिन परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। परीक्षण के सफल परिणाम से इसकी विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और सामरिक उपयोगिता की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य अभियानों के दौरान सैनिकों और आवश्यक संसाधनों की तेजी से तैनाती बेहद महत्वपूर्ण होती है।

बस और ट्रक की टक्कर, 6 की मौत

सूर्यपेट, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। सूर्यपेट जिले में बुधवार सुबह एक इलेक्ट्रिक बस ने पीछे से ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 महिलाएं हैं। वहीं 12 लोग घायल हैं। बस में 43 यात्री सवार थे और यह हैदराबाद से आंध्रप्रदेश के एलुरु जा रही थी। हादसा सुबह करीब 5:15 बजे हैदराबाद-विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर कोडाड मंडल में हुआ। पुलिस ने बताया कि ट्रक में लोहे के भारी पिलर लट्टे थे।

बस के ट्रक से टकराते ही पिलर को बांधकर रखने वाली चेन टूट गई। इसके बाद पिलर बस की दाई तरफ जा घुसे। पुलिस के मुताबिक, बस के आगे बैठे लोगों की इसी वजह से मौत हुई। हादसे की वजह तेज रफ्तार होने की आशंका जताई है। बस की टक्कर से पहले ट्रक के सड़क के डिवाइडर से टकराने की भी आशंका है। पुलिस ने बताया कि घायलों में से दो की हालत गंभीर है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा के एक अस्पताल में भेजा गया है।

सूर्यपिट सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जताया दुख

हैदराबाद, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। सूर्यपेट जिले में हुए भीषण सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गहरा दुख और सदमा व्यक्त किया है। कोडाड मंडल के द्वारकुटा के पास एक निजी बस के कंटेनर से टकराने से यह दुर्घटना हुई। मुख्यमंत्री ने हादसे में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी प्रगाढ़ संवेदना जताई।

उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के साथ सरकार पूरी संवेदना के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि दुर्घटना में घायल लोगों को तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उनके उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखने तथा आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

आईएस-आईपीएस में बदलाव से मचेगी अफरा-तफरी

केंद्र ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट में दी बड़ी दलील

नई दिल्ली, 26 अगस्त (एजेंसियां)। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 'क्रीमी लेयर' के नियम तय करने के लिए दो साल का समय मांगा है। साथ ही, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की बेंच से 11 मार्च के उस फैसले को पिछली तरीख से लागू करने के खिलाफ अपनी अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की है। इस फैसले में पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले माता-पिता की सैलरी के आधार पर ओबीसी उम्मीदवारों के वर्गीकरण (क्रीमी लेयर) को खारिज कर दिया गया था।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच से रोहित नाथन मामले में 11 मार्च के फैसले पर कुछ स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी को लिस्ट करने का अनुरोध किया। वकील वक्कण ठाकुर ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कानून तय कर चुका है।

केंद्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा या उसमें बदलाव नहीं चाहता, बल्कि कोर्ट को पिछली तरीख से इसे लागू करने में आने वाली व्यावहारिक दिक्कों



चालू हैं और पांच निर्माणधीन है।

सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ ?

नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की सूचना स्थानीय समयानुसार सुबह करीब नौ बजे मिली। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ का पानी तिब्बत की ओर से आया प्रतीत होता है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में तिमुरे और स्याब्रुबेसी की सीमावर्ती बस्तियां

शामिल हैं। अधिकारियों ने अभी तक विनाश की पूरी सीमा का पता नहीं लगाया है और न ही हताहतों की पुष्टि की है। क्योंकि आकलन दल अभी भी प्रभावित क्षेत्रों से जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

रसुवा प्रशासन ने क्या कहा ?

रसुवा जिले के प्रशासन नरेंद्र परिवार ने रॉयटर्स को बताया, 'हमें गांवों और बुनियादी ढांचा परियोजना स्थलों के बह

जाने की खबरें मिली हैं। उन्होंने आगे कहा, 'भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता।'

नेपाल सेना ने क्या बताया ?

नेपाल सेना ने कहा कि बाढ़ के कारण तिमुरे और स्याब्रुबेसी क्षेत्र में व्यापक तबाही हुई है, जिसमें वाहन, व्यावसायिक सामान और अन्य संपत्ति पानी में बह गई है। रसुआ के मुख्य सीमा शुल्क अधिकारी राजेंद्र दुंगाना ने बताया कि सीमा शुल्क परिसर में रखे कई वाहन और सामान बह गए। हाल ही में निर्मित एक पुल भी नष्ट हो गया। काठमांडू से लगभग 125 किलोमीटर दूर स्थित और तिब्बत से सटे पहाड़ी जिले रसुवा की आबादी लगभग 50,000 है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने क्या चेतावनी दी ?

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, चितवन और गोरखा में नदी तटों के पास रहने वाले निवासियों को सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की चेतावनी दी है।



के बारे में बताना चाहता है।

ओबीसी उम्मीदवारों के पुराने बैच का स्टेटस बदलना होगा : एसजी टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इसके लिए 'क्रीमी लेयर' ओबीसी उम्मीदवारों के पुराने बैच का स्टेटस बदलकर 'नॉन-क्रीमी' करना होगा और सिविल सर्विस में उनके कैडर, पद और सर्विस में बदलाव करना होगा। इससे आईएफएस, आईएसएस और आईपीएस जैसे कैडर और सर्विस में लंबे समय से काम कर रहे उतने ही उम्मीदवारों के लिए भी इसी तरह के बदलाव करने होंगे, जिससे अफरातफरी मच जाएगी।

आईएफएस, आईएसएस और आईपीएस जैसे कैडर और सर्विस में लंबे समय से काम कर रहे उतने ही उम्मीदवारों के लिए भी इसी तरह के बदलाव करने होंगे, जिससे अफरातफरी मच जाएगी। ओबीसी उम्मीदवारों के पुराने बैच का स्टेटस बदलकर 'नॉन-क्रीमी' करना होगा और सिविल सर्विस में उनके कैडर, पद और सर्विस में बदलाव करना होगा। इससे आईएफएस, आईएसएस और आईपीएस जैसे कैडर और सर्विस में लंबे समय से काम कर रहे उतने ही उम्मीदवारों के लिए भी इसी तरह के बदलाव करने होंगे, जिससे अफरातफरी मच जाएगी।

सीजेआई ने 1 सितंबर को अर्जियों को लिस्ट करने पर सहमति जताई।



सुबह-सुबह भूकंप के झटके 3 सेकेंड तक कांपी धरती

शिमला, 26 अगस्त (एजेंसियां)। हिमाचल प्रदेश में बुधवार सुबह तड़के भूकंप के झटकों से लोग सहम गए। सुबह 5 बजकर 46 मिनट पर महसूस किए गए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 दर्ज की गई। हालांकि इस घटना में जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार भूकंप का केंद्र शिमला से करीब 66 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण दिशा में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके करीब तीन सेकेंड तक महसूस किए गए। अचानक धरती हिलने से कई लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए और खुले स्थानों पर पहुंच गए। कंपन शमने के कुछ देर बाद लोग वापस अपने घरों में लौटे। शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और मंडी के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने की सूचना है। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

‘इस्लामी किताबें पढ़ो, नहीं तो बेटे को आतंकियों को बेच दूंगा’

एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत पर खुला शूटिंग कोच सादिक का काला सच



राजमुंदरी, 26 अगस्त (एजेंसियां)। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी स्थित गोदावरी नदी के रोड-कम-रेलवे पुल से कूदकर एक ही परिवार के तीन सदस्यों द्वारा की गई खुदकुशी के सनसनीखेज मामले में रंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस दर्दनाक घटना के पीछे एक शूटिंग कोच सादिक खान का खोफनाक चक्रव्यूह था। आरोपी ने परिवार पर धर्मांतरण का दबाव बनाया, संपत्ति हड़पी और ब्लैकमेल किया। आंध्र प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने पांच राज्यों में छानबीन के बाद आरोपी सादिक खान की उ्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। काकीनाडा कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना 17 अगस्त की देर रात की है। पिठापुरम में पंचायती राज विभाग में कार्यरत 61 वर्षीय अस्मिस्टेट इंजीनियर थिल्लापुडी नूकाराजू, उनकी 58/59 वर्षीय पत्नी मीना और 34/38 वर्षीय बेटी कोव्वूरी

अवैध रेत व्यापारियों से पैसा वसूलने के आरोप में पुलिस कांस्टेबल और तीन दलाल गिरफ्तार, 5.70 लाख नकद बरामद

झारग्राम, 26 अगस्त (एजेंसियां)। पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में एंटी-कorrप्शन ब्रांच (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने अवैध रेत व्यापारियों से रंगदारी वसूलने के आरोप में झारग्राम पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। झारग्राम पुलिस स्टेशन के गिरफ्तार किए गए आरोपी कांस्टेबल की पहचान रतन प्रमाणिक के रूप में हुई है। उसके साथ ही अवैध रेत कारोबारियों के तीन दलालों—शांतनु बारिक, दीपांकर बारिक और रवि बारिक (सभी निवासी: श्यामसुंदरपुर गांव, बांधगोरा ग्राम पंचायत) को भी दबोचा गया है। आरोपियों के पास से 5 लाख 70 हजार रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के एंटी-कorrप्शन डिपार्टमेंट को शिकायत मिली थी कि झारग्राम थाने का एक कांस्टेबल दलालों के जरिए रेत ढोने वाले ट्रकों और ट्रैक्टरों से अवैध वसूली करवा रहा है। इस शिकायत के आधार पर एसीबी ने एक जाल बिछाया, जिसमें तीनों दलाल ट्रक मालिकों से रिश्तत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। पूछताछ

अंकित शर्मा हत्याकांड

उम्रकैद के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा ताहिर हुसैन, अगले हफ्ते सुनवाई



नई दिल्ली, 26 अगस्त (एजेंसियां)। 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में इंटीलजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़दूमा कोर्ट ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं अब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी सजा और उम्रकैद के फैसले को चुनौती दी है। कोर्ट ताहिर हुसैन की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। अंकित शर्मा की हत्या 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दलालपुर इलाके में हुई थी। बाद में उनका क्षत-विक्षत शव एक नाले से बरामद किया गया था। 3 जुलाई को कड़कड़दूमा की एक अदालत ने ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को इस मामले में दोषी ठहराया।

31 जुलाई को कोर्ट ने सभी पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर 5 लाख रुपये और बाकी दोषियों पर 25,000 रुपये का

लोकसभा सचिवालय ने 20 बागी टीएमसी सांसदों को नोटिस भेजे 7 दिन में जवाब मांगा ; सुप्रीम कोर्ट ने भी कल नोटिस जारी किया था

नई दिल्ली, 26 अगस्त (एजेंसियां)। लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को तुणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को नोटिस भेजे हैं। सांसदों से टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की अयोग्यता याचिका पर 7 दिन में जवाब मांगा गया है। यह याचिका दल-बदल कानून के तहत दाखिल की गई है। नोटिस 25 अगस्त को जारी किए गए और इनमें बनर्जी की 18 जून की याचिका की कॉपी भी भेजी गई है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार होने के एक दिन बाद हुई है। कोर्ट ने मंगलवार को 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया था, लेकिन लोकसभा स्पीकर के कार्यालय और सदन के इहासचिव को नोटिस जारी नहीं किया। अभिषेक बनर्जी ने पहले 20 सांसदों के खिलाफ अलग-अलग अयोग्यता याचिकाएं दाखिल की थीं। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही



जल्द पूरी करने की मांग की थी। बनर्जी की याचिका में शामिल सांसदों के नाम हैं काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंद्योपाध्याय, शताब्दी रॉय, प्रसून बनर्जी, रचना बनर्जी, जगदीश चंद्र बरमा बासुनिया, पार्थ भौमिक, अरूप चक्रवर्ती, अधिकारी दीपक देव, सयानी घोष, बापी हलदर, एमडी अबु ताहेर खान, कालीपद सारेन खेरवाल, असीत कुमार मल, जून

पत्नी को घर के काम करने का हुक्म नहीं दे सकता पति

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सास-ससुर की सेवा पर भी कही ये बात

बेंगलूरू, 26 अगस्त (एजेंसियां)। पति अपनी पत्नी को घर के कामों को करने का हुक्म नहीं दे सकता है। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी एक केस में फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने की है। पति-पत्नी के घरेलू विवाद के मामले में सुनवाई कर रही जस्टिस डॉ. चिल्लाकुर सुमलता ने साफ कहा कि पति अपनी पत्नी को घर के काम करने या सास-ससुर की सेवा करने का आदेश नहीं दे सकता। पत्नी द्वारा पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और भरण-पोषण के मामले में पत्नी पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों और पति पक्ष की सफाई सुनने के बाद अदालत ने कहा कि ऐसे बयान पढ़कर लगता है जैसे पति ने पत्नी को नौकरानी की तरह रख लिया हो, जो सिर्फ घर का काम करे और उसके माता-पिता की देखभाल करे और उसके आदेशों का पालन करे।

माता-पिता की सेवा करना बेटे और बेटियों का कर्तव्य है, न कि सास और ससुर की सेवा के लिए बहू और दामाद पर दबाव डाला जाए। खबर के मुताबिक अदालत ने विवाह की असलिखत पर टिप्पणी करते हुए कहा, “विवाह एक पवित्र और सुंदर बंधन है जो दो व्यक्तियों को जोड़ता है। रीति-रिवाज निभाने से वे सिर्फ पति-पत्नी बनते हैं। लेकिन प्यार, विश्वास, सम्मान, एक-दूसरे का सहारा और भावनाओं



को समझने से वे आत्मीय साथी बनते हैं।” बता दें कि कर्नाटक के फैमिली कोर्ट में पत्नी ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और भरण-पोषण का केस किया था। जिस पर परिवार अदालत ने पति को पत्नी को हर महीने 5,000 रुपये और नाबालिग बेटी को 4,000 रुपये यानी कुल 9,000 रुपये देने का आदेश दिया था। हालांकि पति ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब मामले की सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने पति को याचिका खारिज करते हुए न केवल परिवार अदालत के आदेश की बरकरार रखा बल्कि अदालत ने कहा कि आज की महंगाई और जीवन की लागत को देखते हुए 150 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन बहुत कम है। इतने पैसे में न्यूनतम जरूरतों को भी पूरा करना मुश्किल है। इसलिए भरण-पोषण की रकम घटाने या बदलने का कोई आधार नहीं

(एनसीपीआई) में विलय हो चुका है। बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने 17 जून 2026 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपने के बाद इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा- हम पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे।

बागी सांसद अलग गुट की मान्यता चाहते हैं बागी सांसदों के समूह ने लोकसभा में अलग गुट के तौर पर मान्यता मांगी है। टीएमसी का कहना है कि ये सांसद उसके चुनाव चिह्न पर चुने गए थे। पार्टी के मुताबिक, किसी दूसरे राजनीतिक संगठन में शामिल होने का उनका फैसला दल-बदल कानून के प्रावधानों के तहत आता है। स्पीकर और लोकसभा महासचिव को भी याचिका में प्रतिवादी बनाया गया था। हालांकि, तुषार मेहता की दलील के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ औपचारिक नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया।

कूरियर से कनाडा भेजी जा रही थी अफीम, बदले में मिल रहे थे हथियार ; दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश

नई दिल्ली, 26 अगस्त (एजेंसियां)। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग स्मगलिंग और हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि भारत से कूरियर के जरिए कनाडा अफीम भेजी जा रही थी और इसके बदले में खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों के लिए हथियार मंगाए जा रहे थे। यह पूरा नेक्सस नामित खालिस्तानी आतंकी अशदीप सिंह गिल उर्फ अशं डाला द्वारा चलाया जा रहा था, जो खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) का प्रमुख है। विशेष पुलिस आयुक्त (क्राइम) एचजीएस धालीवाल ने बताया कि इस रैकेट का मकसद केटीएफ की आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग और हथियार जुटाना था। पुलिस ने महीने भर चले इस ऑपरेशन में गिरोह के चार सदस्यों—सिमरनजीत सिंह, हरदीप सिंह, यादविंदर सिंह उर्फ जशन संधू और जीवन सिंह को गिरफ्तार किया है।

जोगी रमेश की बहू ने पूर्व मंत्री और उनके परिवार पर शादी से पहले अपना धर्म छिपाने का आरोप लगाया अमरावती, 26 अगस्त (एजेंसियां)। पूर्व मंत्री जोगी रमेश की बहू मेघना ने उन पर और उनके परिवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने शादी से पहले अपने ईसाई धर्म को छिपाया, उन पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाला और हिंदू देवी-देवताओं व रीति-रिवाजों के बारे में अपमानजनक बातें कहीं।

मेघना ने आरोप लगाया कि शादी से पहले परिवार ने खुद को हिंदू बताया था, लेकिन शादी के बाद घर से हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरें हटा दीं। उन्होंने दावा किया कि पूजा-पाठ करने की इजाजत मांगने के बावजूद, उन्हें केवल एक छोटा सा कमरा दिया गया और उनके धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि जोगी रमेश और उनके परिवार ने शादी से पहले उनके पति राजीव से जुड़ी समस्याओं को छिपाया था। उनके अनुसार, राजीव ने दो महीने के भीतर ही तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। मेघना ने आरोप लगाया कि उनकी सास शकुंतला ने समस्या के बारे में जानने के बावजूद उन पर अहं दहेज लाने का दबाव डाला। उन्होंने सवाल उठाया कि राजीव की स्थिति के बारे में पता होने के बावजूद परिवार ने शादी क्यों तक की। मेघना ने कहा कि उनके पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए वीडियो और अन्य सबूत हैं और वह सही समय पर उन्हें सबके सामने लाएंगी।

एनएच-365बीबी के 840 करोड़ रुपये के अपग्रेड से खेत-से-बाज़ार तक कनेक्टिविटी और पोलावरम तक पहुंच बेहतर होगी

विजयवाड़ा, 26 अगस्त (एजेंसियां)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश में नेशनल हाईवे-365बीबी के अहम हिस्सों को अपग्रेड करने के लिए 840.41 करोड़ रुपये की मंजूरी की घोषणा की है। इसका मकसद इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और खेत-से-बाज़ार तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इस प्रोजेक्ट में एनएच-365बीबी के बूढ़ाईगुडेम-एलगुनडी पेठा और पट्टिसीमा-कोव्वुर हिस्सों को मिलाकर 45.09 किलोमीटर लंबे रास्ते को पक्के शोल्डर (सड़क के किनारे की जगह) के साथ दो-लेन वाले हाईवे में बदलना शामिल है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, अपग्रेड किए गए हाईवे से पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट और आस-पास के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच काफी बेहतर हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट तंबाकू, गन्ना और पाम ऑयल जैसे कृषि उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन को तेज़ करेगा, जिससे स्थानीय किसानों के लिए लॉजिस्टिक्स मजबूत होंगे और पूरे इलाके में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। खेती से जुड़े फायदों के अलावा, अपग्रेड किया गया कॉरिडोर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच



अंतर-राज्यीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, जिससे यात्रियों, व्यापार और पर्यटन को फायदा होगा। यह हाईवे गोदावरी नदी के किनारे बने अहम स्नान घाटों तक आसानी से पहुंचने का रास्ता भी देगा, जिससे 2027 में होने वाले गोदावरी पुष्करल के दौरान तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री एन। चंद्रबाबू नायडू ने फंड मंज़ूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट पोलावरम प्रोजेक्ट तक निर्बाध कनेक्टिविटी देगा और साथ ही तंबाकू, गन्ना, पाम और एक्वा (मछली पालन) किसानों के लिए बाजार तक तेजी से पहुंच सुनिश्चित करेगा।

भोपाल में शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग मांगें नहीं मानी तो शिक्षक दिवस से करुंगा 24 घंटे की भूख हड़ताल: दिग्विजय सिंह

भोपाल, 26 अगस्त (एजेंसियां)। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में शिक्षक भर्ती-2025 और रिक्त पदों को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के बीच बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार से जल्द समाधान की मांग की। चेतवनी दी कि यदि मांगें नहीं मानीं गईं तो शिक्षक दिवस से वे खुद 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि उनके जीवन में स्वास्थ्य और शिक्षा हमेशा सबसे महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में स्कूल खोले गए। उनके मुताबिक करीब 45 हजार नए स्कूल खोले गए थे।

साथ ही शिक्षकों की भर्ती का अधिकार भोपाल से हटाकर स्थानीय स्तर पर दिया गया था। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी थे। उन्होंने कहा कि उस समय शिक्षकों की भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाती थी। सिंह ने वर्तमान



सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था और सिलेबस में बदलाव का असर उन शिक्षकों पर पड़ रहा है, जिन्होंने वर्षों तक पुराने सिलेबस के आधार पर पढ़ाया है और अब उन्हें नए सिलेबस के अनुसार परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। रिक्त पदों को लेकर उन्होंने सरकार से सवाल किया कि अखिर सरकार इन पदों पर भर्ती क्यों नहीं कर रही है? आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और रोजगार देने के बजाय युवाओं को दूसरे मुद्दों में उलझाने की है। सिंह ने भाजपा और आरएसएस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में शिक्षा और रोजगार की जगह राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है।

वाईएसआरसीपी नेता जगन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा लोकल बांडी की हर सीट पर चुनाव लड़ें



विजयवाड़ा, 26 अगस्त (एजेंसियां)। पूर्व मुख्यमंत्री और व्आईएसआरसीपी अध्यक्ष व्आईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से आने वाले लोकल बांडी चुनावों में हर सीट पर चुनाव लड़ने को कहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सत्ता में आने के दो साल के भीतर भी मौजूदा गठबंधन सरकार के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी (एंटी-इनकॉबेंसी) पैदा हो गई है। पार्टी कोऑर्डिनेटर्स, 175 विधानसभा क्षेत्रों के इंचार्ज और वरिष्ठ नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से होते हैं, तो समाज के सभी वर्गों में फैली नाराजगी एक निर्णायक चुनावी जीत में बदल सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे

कथित गड़बड़ियों के खिलाफ लड़ें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी सीट बिना चुनाव के न रह जाए। इस बात पर जोर देते हुए कि पार्टी के भीतर निर्विरोध चुनाव बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, जगन ने विधानसभा क्षेत्रों के इच्छुक उम्मीदवारों को निर्देश दिया कि वे लोकल बांडी की सभी सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारें। उन्होंने कहा कि लोकल बांडी चुनावों में मजबूत उपस्थिति बनाए रखने से पार्टी की व्यापक राजनीतिक वापसी की नींव पड़ेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों तक पहुंचने की एक जबरदस्त योजना बताई और नेताओं को घर-घर जाकर व्आईएसआरसीपी के रिकॉर्ड में अंतर बताने का निर्देश दिया। संगठनात्मक अभियान को मजबूत करने के लिए, पार्टी गाँव स्तर तक के कार्यकर्ताओं को व्युआर को वलें वाई आई की कड़ी जारी करने, प्रचार सामग्री बाँटने और जिला, विधानसभा क्षेत्र, मंडल और डिवीजन स्तर पर व्यवस्थित बैठकें आयोजित करने की योजना बना रही है।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अन्नामलाई चलाने जा रहे अभियान, क्या है प्लान?

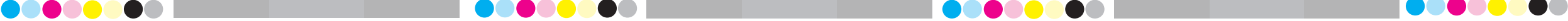
चेन्नई, 26 अगस्त (एजेंसियां)। तमिलनाडु वीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई सितंबर से राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर एक महीने तक चलने वाला जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहे हैं। यह अभियान अन्नामलाई के संगठन ' वी द लीडर्स ' के बैनर तले चलाया जाएगा। यह कैपेन महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके लिए सुरक्षित जगहें बनाने की अहमियत के बारे में लोगों को जागरूक करने पर केंद्रित होगा। उम्मीद है कि संगठन से जुड़े वॉलंटियर पूरे महीने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जागरूकता कार्यक्रम और कम्युनिटी-लेवल की गतिविधियां चलाएंगे। अन्नामलाई ने वीजेपी छोड़ने के बाद 'वी द लीडर्स' शुरू किया। उनके नई राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी की भी खबर है।

अपने राजनीतिक प्लान की औपचारिक घोषणा से पहले, अन्नामलाई संगठन के वॉलंटियर्स की मदद से कई सामाजिक जागरूकता पहल कर रहे हैं। इन कैपेन को तमिलनाडु में लोगों से जुड़ने और जमीनी स्तर पर अपने संगठन की मौजूदगी बढ़ाने की उनकी कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। हर महीने, 'वी द लीडर्स' किसी खास



सामाजिक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करता है और उससे जुड़ी जन-संपर्क गतिविधियां चलाता है। जुलाई में, अन्नामलाई ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बड़ा कैपेन चलाया था। इस पहल का मकसद युवाओं और परिवारों को नशीले पदार्थों से बढ़ते खतरे और नशाखोरी को रोकने में कम्युनिटी की भागीदारी की जरूरत के बारे में जागरूक करना था।

अगस्त के दौरान, संगठन ने अपना ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर लगाया। वॉलंटियर राज्य भर में समुद्र तटों, नदियों और अन्य जल निकायों की सफाई में शामिल रहे हैं। संगठन के अनुसार, इस अभियान के तहत अब तक लगभग 190 टन कचरा हटाया जा चुका है। 'वी द लीडर्स' ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान स्तर पर अपने संगठन की मौजूदगी बढ़ाने की बैनर तले तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में लगभग सात लाख पौधे लगाए गए हैं।



निवेश आकर्षित करने पर जोर, ‘इन्वेस्ट तेलंगाना’ के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन

दिसंबर में होने वाले वैश्विक सम्मेलन की तैयारियों के लिए विशेष युद्ध कक्ष बनाने के निर्देश भट्टी विक्रमार्क की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई



हैदराबाद, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से दिसंबर में आयोजित होने वाले ‘तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट-2026’ और ‘इन्वेस्ट तेलंगाना समिट’ की तैयारियों को सरकार ने तेज कर दिया है। उपमुख्यमंत्री मल्ल भट्टी विक्रमार्क ने अधिकारियों को सम्मेलन की तैयारियों के लिए महात्मा फुले प्रज्ञा भवन में तत्काल विशेष युद्ध

कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए। बुधवार को प्रज्ञा भवन में भट्टी विक्रमार्क की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई। बैठक में मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी, दुहिला श्रीधर बाबू, मुख्य सचिव संजय जाजू सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि युद्ध कक्ष की निगरानी वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में की जाए और मुख्य सचिव इसकी व्यवस्था को

मजबूत बनाएं। उन्होंने सम्मेलन के लिए गठित विभिन्न समितियों में आवश्यक विशेषज्ञों और महत्वपूर्ण अधिकारियों को शामिल करने के निर्देश दिए। पिछले वैश्विक सम्मेलन के दौरान हुए समझौता ज्ञापनों की वर्तमान प्रगति का व्यापक विश्लेषण करने के लिए विशेष समिति गठित करने को भी कहा। भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि दिसंबर में होने वाले सम्मेलन के लिए देश के विभिन्न

हिस्सों के साथ-साथ विदेशों में भी व्यापक निवेशक सम्मेलन और प्रचार यात्राएं आयोजित कर निवेशकों को तेलंगाना की ओर आकर्षित किया जाए। उन्होंने सम्मेलन में आमंत्रित अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी नहीं करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाने चाहिए। मुख्य सचिव प्रतिदिन कम से कम एक घंटे का समय निकालकर तैयारियों की समीक्षा करें और प्रत्येक समिति को सौंपी गई जिम्मेदारियों की नियमित निगरानी करें। उन्होंने अधिकारियों से समन्वय के साथ काम करते हुए सम्मेलन को सफल बनाने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

हुसैन सागर में आत्महत्या की कोशिश करने वाले सूडानी नागरिक को बचाया गया

हैदराबाद, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। बुधवार को डॉ. बी.आर. अंबेडकर सचिवालय के पास हुसैन सागर में कूदकर आत्महत्या की कोशिश करने वाले एक विदेशी नागरिक को सैफबाद पुलिस ने बचाया। यह घटना सचिवालय के सामने हुई, जहाँ झट्टी पर तैनात सैफबाद पुलिसकर्मियों ने उस व्यक्ति को झील में जाते हुए देखा।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रस्सी की मदद से उसे पानी से बाहर निकाला और सुरक्षित बचा लिया। उस व्यक्ति की पहचान सूडानी नागरिक के तौर पर हुई। बचाने के बाद, सैफबाद पुलिस ने उसे आगे की पृष्ठताछ के लिए लेके पुलिस को सौंप दिया।

लेक पुलिस आत्महत्या की कोशिश के कारणों का पता लगाने के लिए उससे पृष्ठताछ कर रही है और घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है।

मी सेवा केंद्र बनेंगे डिजिटल विपणन केंद्र : श्रीधर बाबू

हैदराबाद, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। तेलंगाना के प्रत्येक मी सेवा केंद्र को डिजिटल विपणन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री दुहिला श्रीधर बाबू ने बुधवार को कहा कि स्थानीय व्यापारियों को कम लागत में डिजिटल प्रचार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मी सेवा और मेटा का संयुक्त कार्यक्रम पूरे राज्य में विस्तारित किया जा रहा है। गम्भीरबोली स्थित शेरटन होटल में आयोजित मी सेवा डिजिटल विपणन प्रशिक्षण के दूसरे चरण में विभिन्न जिलों से 140 से अधिक मी सेवा ग्राम स्तरीय उद्यमियों ने हिस्सा लिया।

इन्हें ‘डिजिटल व्यापार दूत’ के रूप में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना नई तकनीक अपनाने में हमेशा अग्रणी रहा है। राज्य में 5,000 से अधिक मी सेवा केंद्र हैं, जिनके माध्यम से मिठाई की दुकानों, कपड़ा प्रतिष्ठानों, कुशल कारीगरों तथा अन्य छोटे कारोबारियों को डिजिटल विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे व्यापारियों की आय बढ़ाने के साथ लोगों में डिजिटल जागरूकता और



रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को पहले हैदराबाद में पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। करीब 120 ग्राम स्तरीय उद्यमियों को डिजिटल विपणन और सामाजिक माध्यमों पर विज्ञापन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इनमें 10 से अधिक उद्यमी अब प्रत्यक्ष रूप से डिजिटल विज्ञापन अभियान चला रहे हैं और स्थानीय व्यापारियों के लिए 17 से अधिक विज्ञापन तैयार कर प्रकाशित कर चुके हैं। पहले चरण के अच्छे परिणामों के बाद कार्यक्रम को सभी जिलों में विस्तारित किया जा रहा है। दूसरे चरण में प्रत्येक जिले से चार से पांच ग्राम स्तरीय उद्यमियों

का चयन किया गया है। प्रशिक्षित उद्यमी अपने जिलों में स्थानीय कारोबारियों की जरूरत समझने, डिजिटल विपणन के लाभ बताने, विज्ञापन तैयार करने और लक्षित ग्राहकों तक पहुंच बनाने में सहायता करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रीधर बाबू की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और मेटा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मी सेवा आयुक्त एवं इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण अधिकारी टी. रविकिरण, भारतीय वन सेवा अधिकारी, मेटा के प्रबंध निदेशक एवं देश प्रमुख अरुण श्रीनिवास, रणनीतिक कार्यक्रम एवं साझेदारी प्रमुख दिव्या खेमानी वधेरा तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने स्थानीय व्यापारियों के लिए नई सुविधा, पोर्टल और सहायता सेवा भी शुरू की।

व्यापारी मी सेवा के माध्यम से डिजिटल विपणन सहायता प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित डिजिटल विपणन ग्राम स्तरीय उद्यमी उपलब्ध हों। स्थानीय व्यापारियों को कम लागत में डिजिटल प्रचार की सुविधा मिले।

दुर्ब पुलिस ने तेलंगाना के युवाओं को फ़र्जी वीज़ा और नौकरी के ऑफ़र से सावधान रहने को कहा

हैदराबाद, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। दुर्ब पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने और वीज़ा व नौकरी के ऑफ़र के झूठे वादों से गुमराह न होने की अपील की है। पुलिस लोगों को लगातार सचेत करती रहती है क्योंकि स्कैमर्स (धोखाधड़ी करने वाले) नौकरी चाहने वालों को फ़र्जी वर्क वीज़ा और नौकरी के ऑफ़र का लालच देकर निशाना बनाते हैं। धोखेबाज़ पक्षी नौकरी या वीज़ा स्पॉन्सरशिप का वादा करते हैं, जिनका कोई कानूनी आधार नहीं होता, और अक्सर पहले ही पैसे की मांग करते हैं। दुर्ब पुलिस के अपराधिक जांच विभाग के एंटी-फ़्राड सेंटर ने पैसे के बदले काम, रेजिडेंसी या विज़िट वीज़ा देने का वादा करने वाले फ़र्जी विज्ञापनों और संदेशों की बढ़ती

संख्या के बारे में चेतावनी जारी की है। ध्यान देने वाली बात है कि तेलंगाना के युवा उन लोगों में शामिल हैं जो अक्सर ऐसे घोटालों का शिकार हो जाते हैं। ये धोखेबाज़ विज्ञापन सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप पर शेर किए जा रहे हैं। इनमें अक्सर बिना लाइसेंस वाली कंपनियों के नाम का इस्तेमाल किया जाता है या खुद को आधिकारिक संस्था बताकर लोगों को ठगा जाता है और उनके पैसे हड़प लिए जाते हैं। अपने चल रहे धोखाधड़ी से सावधान रहें: जागरूकता अभियान के तहत, सेंटर ने सभी वीज़ा आवेदन अधिकृत और कानूनी रूप से लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों के ज़रिए जमा करने और बिचौलियों या अविश्वसनीय स्रोतों के साथ लेन-

देन से बचने के महत्व पर ज़ोर दिया है। इसने वीज़ा से जुड़े किसी भी ऑफ़र या प्रक्रिया की असंख्यता की पुष्टि सिर्फ आधिकारिक चैनलों के ज़रिए करने की जरूरत पर भी ज़ोर दिया। सेंटर ने कहा कि जागरूकता और सर्विस देने वाले स्रोतों की पुष्टि करना धोखाधड़ी से बचाव का पहला कदम है। साथ ही, लोगों से सतर्क रहने और गैर-कानूनी तरीकों से वीज़ा या नौकरी पाने के झूठे वादों से बचने की अपील की। लोगों को यह भी साफ तौर पर चेतावनी दी गई कि वे कानूनी चैनलों के बाहर मिलने वाले वीज़ा या नौकरी के वादों या गारंटी से गुमराह न हों। सेंटर ने इन्हें नौकरी या रेजिडेंसी चाहने वाले लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए बनाए गए गुमराह करने वाले वादे बताया।

32 महीने से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे दिवंगत शिक्षकों के परिवार : हरीश राव

पूर्व मंत्री ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले शिक्षकों के परिजनों से मुलाकात की

हैदराबाद, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। पूर्व मंत्री एवं बीआरएस के उप सदन नेता हरीश राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की लापरवाही के कारण मांडल स्कूलों के शिक्षक और उनके परिवार गंभीर आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार को शिक्षक संघ के नेताओं तथा झट्टी के दौरान जान गंवाने वाले शिक्षकों के परिजनों ने उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताईं। हरीश राव ने कहा कि पिछले 32 महीनों से प्रभावित परिवार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई संवेदनशील पहल नहीं की गई। उन्होंने इसे रेवंत रेड्डी सरकार के अमानवीय रवैये का प्रमाण



बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 के बाद अंशदायी पेंशन प्रणाली के तहत नियुक्त होकर जान गंवाने वाले करीब 40 मांडल स्कूल शिक्षकों के परिवारों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है।

सरकारी आदेश संख्या 60 और 58 के अनुसार इन परिवारों को मृत्यु उपदान और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की पूरी पात्रता है, लेकिन

सरकार द्वारा इन आदेशों को मांडल स्कूलों में लागू नहीं किए जाने के कारण प्रभावित परिवार बेसहारा हो गए हैं। हरीश राव ने सरकार से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने हुए दिवंगत शिक्षकों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति के तहत रोजगार देने की मांग की। साथ ही उन्होंने राज्य के सभी मांडल स्कूल शिक्षकों के लिए मृत्यु उपदान और

पारिवारिक पेंशन की सुविधा लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अधिकारियों को सैकड़ों आवेदन दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

शिक्षा विभाग का दायित्व संभाल रहे मुख्यमंत्री को इस लापरवाही की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हरीश राव ने कहा कि राज्य के 194 मांडल स्कूलों में कार्रवाई करीब 3,000 शिक्षकों के पांच मंहगाई भत्ते लंबित रखकर सरकार उन्हें आर्थिक संकट में डाल रही है। उन्होंने बताया कि लंबित मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने 93 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मांग की थी, लेकिन सरकार ने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।

सूर्यापट सड़क हादसे पर हरीश राव ने जताया गहरा दुख

घायलों को बेहतर उपचार देने की मांग हैदराबाद, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। सूर्यापट जिले के कोदाड़ मंडल के दुर्गापुरम स्ट्रेज के पास हुए भीषण सड़क हादसे पर बीआरएस विधायक दल के उपनेता एवं पूर्व मंत्री हरीश राव ने गहरा दुख और सदमा व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में कई यात्रियों की मौत होना बेहद पीड़ादायक है। हरीश राव ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अचानक हुई इस दुर्घटना से अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों का दुख अत्यंत गंभीर है।

गांधी भवन भी बना जनता की समस्याओं के समाधान का मंच : वी. हनुमंत राव



हैदराबाद, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। तेलंगाना सरकार के सलाहकार वी. हनुमंत राव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रगति भवन को जनता के लिए खोलकर उसे जनता भवन में परिवर्तित किया और अब गांधी भवन को भी लोगों की समस्याओं के समाधान का मंच बनाया जा रहा है। गांधी भवन में आयोजित ‘जनता से आमने-सामने’ कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में प्रगति भवन बनाया गया था, जहां आम लोगों को अपनी समस्याएं बताने का अवसर नहीं मिलता था।

कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रगति भवन को जनता भवन में बदलकर उसे लोगों की समस्याओं के समाधान का केंद्र बनाया गया। हनुमंत राव ने कहा कि इसी उद्देश्य से गांधी भवन में भी ‘जनता से आमने-सामने’ कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि आम लोग सीधे अपनी समस्याएं सरकार और पार्टी के प्रतिनिधियों के सामने रख सकें। उन्होंने बताया कि बुधवार को उनके

सामने बड़ी संख्या में भूमि संबंधी समस्याएं आईं। उन्होंने कहा कि पहले पटेल-परवारी व्यवस्था के दौरान भूमि विवाद अपेक्षाकृत कम थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के कार्यकाल में धरणी व्यवस्था के साथ कई नई समस्याएं सामने आईं। हनुमंत राव ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गरीबों को वितरित की गई जमीनों को भी कुछ भूमिस्वामी

दोबारा अवैध रूप से अपने नाम पंजीकृत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकरण कार्यालयों में भी कई तरह की गलतियां हो रही हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य के राजस्व मंत्री से भूमि और पंजीकरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मांग की।

एथिक्स कमेटी को राजनीतिक हथियार न बनाए सरकार : वेमुला प्रशांत रेड्डी

पहले मुख्यमंत्री, मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों के आचरण की हो जांच

हैदराबाद, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। बीआरएस के पूर्व मंत्री एवं विधायक वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी सरकार विभिन्न समितियों के नाम पर विपक्षी सदस्यों को परेशान कर रही है। तेलंगाना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पांडी कौशिक रेड्डी के व्यवहार पर चर्चा के लिए 29 अगस्त को एथिक्स कमेटी की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या एथिक्स कमेटी केवल विपक्षी सदस्यों पर कार्रवाई करने के लिए बनाई गई है। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पांडी कौशिक रेड्डी के मामले को एथिक्स कमेटी को भेजने की बात कही थी, जबकि उस समय ऐसी कोई समिति अस्तित्व में नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले निर्णय लेकर समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि कौशिक रेड्डी ने विधानसभा में तत्कालीन



घटनाक्रम के दौरान केवल कडियम श्रीहरि से पूछा था कि वे किस पार्टी में हैं, लेकिन उनके पक्ष के गलत तरीके से पेश कर मामला समिति को भेजा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के नेताओं के कथित आपत्तिजनक व्यवहार पर समिति मौन है। दानम नागेंद्र, कांग्रेस विधायक मंदुला शम्भूलाल, पोन्नम प्रभाकर, शादनगर के शंकरैया और वेमुला वीरसम के विधानसभा में कथित व्यवहार का उल्लेख करते

हुए उन्होंने पूछा कि इन मामलों पर एथिक्स कमेटी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। प्रशांत रेड्डी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर भी विधानसभा में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया और कहा कि सबसे पहले मुख्यमंत्री को समिति के समक्ष बुलाकर स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद ही कौशिक रेड्डी से पृष्ठताछ हो। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एथिक्स कमेटी को राजनीतिक समिति में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए कथित प्रष्टाचार के आरोपों की भी जांच कराने की मांग की। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस विधायक 29 अगस्त की समिति बैठक में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा कांग्रेस विधायकों को पहले जांच के लिए बुलाने की मांग करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार प्रतिशोध की राजनीति बंद करे।

स्वतंत्र वार्ता

गुरुवार, 27 अगस्त - 2026

ईरान पर आर्थिक वार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ व्यापक आर्थिक प्रतिबंधों की बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे ‘इकनॉमिक डी-डे’ का नाम दिया है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ‘ऑपरेशन इकनॉमिक आउटकास्ट’ के तहत ईरान से कारोबार करने वाली संस्थाओं पर नए, प्रतिबंधों का एलान किया है। निशाने पर डिजिटल परिसंपत्तियां, प्रौद्योगिकी, सोना, विमानन और नौवहन जैसे क्षेत्र हैं। करीब 60 संस्थाओं को प्रतिबंधों के दायरे में लाया गया है, जिनमें चार भारतीय संस्थाएं भी शामिल हैं। अमेरिका का उद्देश्य साफ है ईरान की अर्थव्यवस्था के उन स्रोतों को काटना, जिनसे उसे विदेशी मुद्रा मिलती है। लेकिन इस अभियान की असली परीक्षा ईरान से ज्यादा चीन के मोर्चे पर होनी है। ईरान से निर्यात होने वाला लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल चीन खरीदता है। चीन की छोटी ‘टीपॉर्ट’ रिफाइनरियां ईरानी तेल की बड़ी खरीदार रही हैं। दोनों देशों के बीच कारोबार में युआन का इस्तेमाल बढ़ा है और वैकल्पिक भुगतान व्यवस्थाओं ने अमेरिकी डॉलर आधारित वित्तीय तंत्र से बचने के रास्ते बनाए हैं। यही कारण है कि ईरान को आर्थिक रूप से पूरी तरह अलग-थलग करना अमेरिका के लिए कठिनाई भरा कदम होगा। अमेरिका की रणनीति की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जिस देश पर दबाव डाला जा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण बाहरी सहारा चीन है। अगर वाशिंगटन चीन की बड़ी कंपनियों, बैंकों और तेल खरीदारों पर व्यापक द्वितीयक प्रतिबंध लगाता है तो मामला ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। चीन पहले ही संकेत दे चुका है कि उसके ईरान के साथ आर्थिक संबंधों को अमेरिकी प्रतिबंधों के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश का वह विरोध करेगा। इसलिए ट्रंप प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है—ईरान पर अधिकतम दबाव बनाए रखना और चीन के साथ टकराव को खतरनाक स्तर तक पहुंचने से रोकना। अमेरिका पहले ही ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बढ़ा चुका है। करीब छह महीने तक चले अमेरिका-इजरायल के हमलों के बावजूद तेहरान को निर्णायक रूप से झुकाया नहीं जा सका। न ईरान की सत्ता बदली, न उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाएं खत्म हुईं और न ही होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी खुल सकी। ऐसे में प्रतिबंधों को निर्णायक हथियार मानना स्वाभाविक है, लेकिन आर्थिक दबाव और राजनीतिक परिणाम को एक मान लेना जोखिम भरा है। इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है। ईरान यदि दबाव बढ़ने पर तेल आपूर्ति या होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावित करता है तो कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। इसका असर भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों पर भी पड़ेगा। भारतीय संस्थाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण नई दिल्ली को ऊर्जा सुरक्षा, ईरान के साथ अपने हितों और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी के बीच संतुलन साधना होगा। इसलिए ‘इकनॉमिक डी-डे’ को केवल ईरान के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई समझना भूल होगी। यह अमेरिका की उस क्षमता की भी परीक्षा है, जिसके जरिए वह अपनी विशाल वित्तीय ताकत और कूटनीतिक प्रभाव को पूरी दुनिया पर लागू करना चाहता है। यदि चीन अमेरिकी दबाव के बावजूद ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार बना रहता है तो प्रतिबंधों की धार कमजोर पड़ सकती है। यदि अमेरिका चीन को भी कठोरता से निशाना बनाता है तो वैश्विक व्यापार और वित्तीय व्यवस्था में नया टकराव पैदा हो सकता है। ट्रंप प्रशासन को समझना होगा कि आर्थिक युद्ध में लक्ष्य सिर्फ विरोधी को कमजोर करना नहीं होता; यह भी देखना पड़ता है कि दबाव की कीमत खुद के लिए कितनी भारी पड़ सकती है।

त्योहारों पर भी बाजार सूने घटती क्रय शक्ति और आर्थिक मंदी का गहराता संकट

उत्तर भारत के प्रसिद्ध त्योहार रक्षाबंधन, ईद के साथ-साथ राजस्थान के प्रमुख लोक मेलों—बाबा रामदेव जयंती और गोगाजी मेले का समय है। अमूमन इन अवसरों पर बाजारों में खासी चहल-पहल रहती है, लेकिन इस बार का नजारा बिल्कुल अलग है। बाजार सूने पड़े हैं और छोटे दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में खाली बैठकर समय बिताने को मजबूर हैं। दुकानदारों से थोड़ी देर बातचीत करते ही उनका दर्द छलक आता है; कई व्यापारी तो अपना दैनिक खर्च तक नहीं निकाल पा रहे हैं।



सरदूल सिंह

भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है लेकिन मानसून की बेरुखी और खाद, बीज, कीटनाशक व ईंधन पर कॉर्पोरेट नियंत्रण के कारण कृषि लागत लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा और कालाबाजारी के कारण फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान किराए जैसे अनिवार्य खर्चों में वृद्धि के कारण लोगों को त्योहारों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के बजट में कटौती करनी पड़ रही है। नतीजतन, दुकानों पर 'सेल' के बोर्ड लगाने और भारी प्रचार के बावजूद बिक्री नहीं बढ़ रही है।

आर्थिक मंदी का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र का सिमटना और रोजगार के अवसरों का खत्म होना है। रक्षाबंधन पर पीहर आने वाली बहनों के प्रति आर्थिक तंगी के कारण बदलते नजरिए के आजकल सोशल मीडिया रील्स के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। व्यंग्यात्मक रील्स में त्योहार के लेन-देन और चीनी जैसी बुनियादी चीजों के महंगे होने पर चुटकियां ली जा रही हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि लोग अब त्योहारों को भी एक आर्थिक मजबूरी के रूप में देखने लगे हैं।

यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि र्विचार हमेशा भौतिक परिस्थितियों को उपज होते हैं। जब भौतिक परिस्थितियां शोषणकारी हों, रोजगार के अवसर सीमित हों और लोगों की आय न बढ़ रही हो, तो उनकी क्रय शक्ति (Purchasing Power) स्वाभाविक रूप से घट जाती है।

ऐसी स्थिति में आम नागरिक न्यूनतम जीवन स्तर पर गुजारा करने और त्योहारों पर कम से कम खर्च करने को विवश होता है। यही कारण है कि त्योहारों के मौसम में भी सड़कें सुस्तान हैं।



राधा रमण

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है; वह नर नहीं, नर-पशु निरा है और मृतक समान है। जो भरा नहीं है भावों से , बहती जिसमें रसधार नहीं; वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने यह पंक्तियां किसी जाति-धर्म अथवा व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं लिखी थीं। ठीक उसी तरह चर्चित उपन्यास ‘आनन्दमठ’ में बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने ‘वंदेमातरम् ... का पद किसी को खुश या नाराज करने के लिए नहीं लिखा था। दोनों देश के दिग्गज साहित्यकार और माटी के लाल रहे हैं। दोनों के जन्म से पहले देश गुलाम था। अपनी माटी से मोह और आजादी का सपना दोनों ने देखा था। दोनों की कविताओं में राष्ट्रवाद कूट-कूटकर भरा था। लेकिन आजादी के 79 वर्ष बाद भी हम किस समाज में जी रहे हैं ? हमें अपने ही पुर्खों की बातों, नीतियों, सोच और कविताओं से दिक्कत क्यों हो रही है ? हम क्यों भूल जाते हैं कि जिस देश को हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बताते नहीं अघाते, उसकी बुनियाद हमारे पुर्खों ने ही रखी थी। हम हर चीज को राजनीतिक नजरिये से ही क्यों देखने के आदी होते जा रहे हैं। हमारे देश के नेता जनता को हिन्दू-मुस्लिम की दरार में क्यों बांटने पर आमादा हैं ? क्या 140 करोड़ नागरिकों का यह देश महज मुद्दीभर नेताओं का है ? क्या नेता समाज में कटुता बांटकर अपनी चुनावी गोटी फिट करने के लिए ही यह सब कर रहे हैं, जो देशहित में कतई नहीं है।

सत्ता में बैठे लोग तो बात का वितंडा बनाएंगे ही, क्योंकि उन्होंने देश की मूलभूत समस्याओं की उपेक्षा नहीं की। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बेरोजगारी का बुरा हाल है। देश में बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो दो जून की



रोटी के मोहताज हैं। फिर भी हमारे नेता शर्मसार नहीं हैं। वे अपनी सुख-सुविधा और वेतन-भत्ते बढ़ाने में मिल-जुलकर भागीदार रहते हैं, लेकिन जनता की भलाई में एकमत नहीं होते। अब ताजा विवाद राष्ट्रगीत के पूरे पदों के गायन को लेकर है। यह राष्ट्रगीत बांग्ला साहित्य के देदीप्यमान हस्ताक्षर बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय के लोकप्रिय उपन्यास ‘आनन्दमठ’ से लिया गया है। ‘आनन्दमठ’ का प्रकाशन 1882 में किया गया था। जिसने भी ‘आनन्दमठ’ का अध्ययन किया है, उसे पता है कि ‘आनन्दमठ’ 1770 में बंगाल के अकाल और 1773 के संन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। उपन्यास के मुताबिक अकाल के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गलत निर्णयों, नियमों और किसानों के शोषण से तत्कालीन सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ जाती है। उपन्यास की कथा के अनुसार सत्यानन्द नामक संन्यासी के नेतृत्व में संन्यासियों की एक सेना का गठन होता है, जिसका उद्देश्य देश को अंग्रेजी कुशासन से मुक्त कराना है। उसी उपन्यास में वंदेमातरम् शीर्षक से कविता की गूंज होती है। बाद में आजादी की लड़ाई में इस कविता ने अहम भूमिका निभायी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदेमातरम् भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए

मिठास का कड़वा गणित : चीनी के भावों के उतार-चढ़ाव का असल खेल



अशोक भाटिया

रसोई का एक आवश्यक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह देश के आर्थिक और राजनीतिक ताने-बाने को नियंत्रित करने वाली एक बेहद संपेदनशील कमोडिटी भी है। हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में आई अचानक उछाल ने एक बार फिर उपभोक्ताओं की जेब पर असर डाला है और नीति-निर्माताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खुदरा बाजार में चीनी के दाम अचानक प्रति किलो कई रुपये चढ़ गए हैं। आम उपभोक्ता के लिए यह केवल एक सामान्य महंगाई की मार हो सकती है, लेकिन राजनीतिक-आर्थिक चश्मे से देखें तो इसके पीछे ‘डिमांड और सप्लाई’ के पारंपरिक नियम से कहीं बड़ा और पेचीदा खेल चल रहा है। इस खेल में मौसम की अनिश्चितता, एथनॉल निर्माण की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय नीतियां, सरकारी अनुमानों के यू-टर्न, अंतरराष्ट्रीय बाजार का दबाव और सबसे बढ़कर, घरेलू बाजार के सटोरियों व रसुखदार जमाखोरों की सिंडिकेट शामिल है। चीनी के इस पूरे चक्रव्यूह को समझें बिना हम इसकी कीमतों के उतार-चढ़ाव के असल खेल को नहीं समझ सकते। चीनी उद्योग का सबसे पहला और बुनियादी खेल गाने की पैदावार बनाना की ‘रिकवरी रेट’ के बीच छुपा होता है। अस्सर आम जनता और यहाँ तक कि सरकारें भी गन्ने की लहलहाती फसल देखकर यह मान लेती हैं कि इस साल चीनी का बंपर उत्पादन होगा। लेकिन हकीकत इसके उलट होती है। इस सीजन में भी गन्ने की फसल खेतों में खड़ी जरूर दिखी, लेकिन मौसम के मिजाज ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। मानसून की अनिश्चितता और एन वक्त पर कपास की शुरुआत में जब मिलों और सरकारी विभागों ने बंपर स्टॉक का अनुमान लगाया, तो सरकार ने चीनी के निर्यात को हरी झंडी दे दी। इसके तहत लगभग २० लाख टन चीनी देश से बाहर भेज दी गईं ताकि मिल मालिकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के ऊंचे दामों का फायदा

चाहता है। वे केवल मुआवजे के बदले अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते। किसानों का यह सवाल गंभीर है कि जमीन चली गई तो खेती और उससे जुड़ी उनकी आर्थिक सुरक्षा का क्या होगा? यहीं से यह मामला महज भूमि अधिग्रहण का प्रशासनिक प्रश्न नहीं रह जाता। इसे महात्मा गांधी और डॉ. राममनोहर लोहिया की कसौटी पर देखने पर विकास, लोकतंत्र और किसान के अधिकार से जुड़े कई बुनियादी प्रश्न सामने आते हैं।



कुमार कृष्णन

इसके पीछे जमीन, आजीविका, सम्मान, अस्मिता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है। प्रस्तावित पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट डाउनशॉप को लेकर पुनपुन, नैबतपुर, मसौड़ी, फतुहा, संपतचक्र, पटना ग्रामीण, धनरुआ, दनियाबां और फुलवारी क्षेत्र के किसानों में असंतोष है। प्रस्तावित योजना का क्षेत्र करीब 81,730 एकड़ और 273 गांवों तक फैला बताया गया है। पुनपुन के 19 गांवों में करीब 3,008 एकड़ का कोर क्षेत्र प्रस्तावित है।

सरकार जैसे पटना के सुनियोजित विस्तार, आवास, रोजगार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में देख रही है। दूसरी ओर किसानों का कहना है कि उनकी बहुफसली और उपजाऊ जमीन ही उनकी आजीविका का

रही थी, वहीं यह रिकवरी रेट गिरने के कारण घटकर लगभग ३०६ लाख टन पर ही सिमट गया। यानी फसल दिखने में अच्छी थी, लेकिन मिलों से निकलने वाली चीनी का वास्तविक उत्पादन उम्मीद से ३७ लाख टन कम रहा। यह उत्पादन का पहला कड़वा सच है जो बाजार में कमी की शुरुआती बुनियाद रखता है।

चीनी के भावों में आए इस उबाल के पीछे सरकार की 'एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी' का भी एक बड़ा रणनीतिक हाथ है। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए सरकार पेट्रोल में २० प्रतिशत तक एथनॉल मिलाने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है। एथनॉल बनाने के लिए सबसे मुफीद और आसान जरिया गन्ने का रस या भारी शीरा होता है। जब चीनी मिलों को गन्ने के रस से सीधे एथनॉल बनाने की अनुमति मिली, तो मिल मालिकों के लिए यह अधिक मुनाफे का सौदा साबित हुआ। बाजार के विश्लेषकों का एक वर्ग यह आरोप लगाता रहा है कि भारी मात्रा में गन्ने के रस को एथनॉल निर्माण की तरफ मोड़ने के कारण घरेलू बाजार में चीनी का स्टॉक कम हुआ और कीमतें बढ़ीं। हालाँकि, सरकार के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि इस साल उत्पादित कुल एथनॉल का लगभग ६८ प्रतिशत हिस्सा मक्का और खराब हो चुके अनाजों से आया है, और चीनी का केवल ९ प्रतिशत हिस्सा ही एथनॉल के लिए इस्तेमाल हुआ। इसके बावजूद, बाजार एक मनोवैज्ञानिक धारणा पर काम करता है। जैसे ही सटोरियों को यह संदेश जाता है कि गन्ना चीनी के बजाय ईंधन बनाने में जा रहा है, वे बाजार में कृत्रिम कमी का डर दिखाकर कीमतों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं।

चीनी के खेल को नियंत्रित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी खुद सरकार की व्यापारिक नीतियां और उनके बदलते आंकड़े हैं। चीनी एक ऐसी कमोडिटी है जिस पर सरकार की पैनी नजर होती है, लेकिन कई बार जमीनी हकीकत को भांपने में होने वाली देरी बाजार को पूरी तरह अस्थिर कर देती है। इस सीजन की शुरुआत में जब मिलों और सरकारी विभागों ने बंपर स्टॉक का अनुमान लगाया, तो सरकार ने चीनी के निर्यात को हरी झंडी दे दी। इसके तहत लगभग २० लाख टन चीनी देश से बाहर भेज दी गईं ताकि मिल मालिकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के ऊंचे दामों का फायदा

शहर बनाइए, लेकिन जिंदगी उजाड़कर नहीं

आधार है। वे केवल मुआवजे के बदले अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते। किसानों का यह सवाल गंभीर है कि जमीन चली गई तो खेती और उससे जुड़ी उनकी आर्थिक सुरक्षा का क्या होगा? यहीं से यह मामला महज भूमि अधिग्रहण का प्रशासनिक प्रश्न नहीं रह जाता। इसे महात्मा गांधी और डॉ. राममनोहर लोहिया की कसौटी पर देखने पर विकास, लोकतंत्र और किसान के अधिकार से जुड़े कई बुनियादी प्रश्न सामने आते हैं।

गांधी के विकास-दर्शन का केंद्र मनुष्य था। वे विशेष रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति के हित को किसी भी निर्णय की कसौटी मानते थे। उनको ‘अंत्योदय’ की दृष्टि यही पूछती है कि किसी नीति या परियोजना का असर सबसे कमजोर व्यक्ति पर क्या पड़ेगा।

पाटलिपुत्र डाउनशिप के संदर्भ में पहला सवाल भी यही होना चाहिए कि इस परियोजना से सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? यदि वह किसान है जिसकी तीन फसलों वाली जमीन चली जाती है, तो उसके जीवन का मूल्यांकन केवल जमीन की बाजार कीमत से कैसे किया

मिल सके और वे किसानों के गन्ने का भुगतान समय पर कर सकें। लेकिन जैसे ही मध्य-सीजन में कम रिकवरी के कारण चीनी का वास्तविक उत्पादन घटने लगा, सरकार को अपनी रणनीति अचानक बदलनी पड़ी। आनन-फानन में निर्यात पर रोक लगाई गई और घरेलू बाजार में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तुरंत १० लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की घोषणा करनी पड़ी। सरकार की नीतियों में आया यह अचानक यू-टर्न बाजार के बड़े व्यापारियों के लिए एक स्पष्ट संकेत होता है। वे समझ जाते हैं कि सरकार के पास स्टॉक की कमी है, और यहीं से सट्टेबाजी का असली खेल शुरू होता है।

जब उद्योग जगत के शीर्ष संगठन ‘इंडियन शुगर एंड बायोएनर्जी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन’ के बयानों को देखा जाए, तो उनका स्पष्ट कहना है कि देश में चीनी की कोई वास्तविक या भौतिक किल्लत नहीं है। देश की आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए गोदामों में पर्याप्त चीनी मौजूद है। तो फिर दाम क्यों बढ़ रहे हैं? इसका जवाब है—जमाखोरी और कृत्रिम किल्लत का संगठित सिंडिकेट। यह खेल थोक व्यापारियों, बड़े डीलरों और वायदा बाजार के सटोरियों द्वारा खेला जाता है। जैसे ही मौसम की खराबी या आनी-जानाई नीतियों में बदलाव की खबरें आती हैं, यह सिंडिकेट सक्रिय हो जाता है। विशेषकर त्योहारों के सीजन के दौरान, जब मिठाई और कोल्ड ड्रिंक निर्माताओं की मांग चरम पर होती है, ये बड़े डीलर एडवांस में ही चीनी का भारी स्टॉक दबा लेते हैं। मिलों से बाजार तक आने वाली स्प्लाई चेन को जानबूझकर धीमा कर दिया जाता है। जब मांग बहुत ज्यादा हो और बाजार में माल कम दिखे, तो कीमतें अपने आप आसमान छूने लगती हैं। इस तरह बिना किसी वास्तविक ‘कमी’ के, केवल कागजी और गोडाउन के स्तर पर कमी दिखाकर करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाया जाता है।

चीनी केवल स्थानीय बाजार की वस्तु नहीं है, यह एक वैश्विक कमोडिटी भी है। जब भी दुनिया की शुरुआत में जब मिलों और सरकारी विभागों ने बंपर स्टॉक का अनुमान लगाया, तो तेजी से बढ़ने लगते हैं। भारतीय चीनी मिलें हमेशा इस फिराक में रहती हैं कि वे वैश्विक बाजार की इस तेजी का लाभ उठाएं।

जा सकता है? किसान के लिए जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं है। वह उत्पादन का साधन, परिवार की सुरक्षा और सामाजिक पहचान का आधार है। खेत से होने वाली आय से बच्चों की पढ़ाई, बेटीयों की शादी और परिवार की दूसरी जरूरतें पूरी होती हैं। इसलिए जमीन के बदले मिलने वाला मुआवजा और आजीविका का स्थायी विकल्प एक ही बात नहीं है। गांधी की कसौटी पर किसी भी विकास योजना को पहली परीक्षा यही होगी कि क्या वह अंतिम व्यक्ति के हित को केंद्र में रखती है।

गांधी की ‘ट्रस्टशिप’ की अवधारणा भी यहां प्रासंगिक है। इसका मूल भाव था कि संसाधनों का उपयोग व्यापक सामाजिक हित में होना चाहिए। यदि कृषि भूमि को शहरी विकास में बदला जाता है तो उस भूमि से जुड़े लोगों को केवल मुआवजे का पात्र मान लेना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें निर्णय-प्रक्रिया का सहभागी बनाना होगा। सरकार की ओर से लैंड पूलिंग, समझौता, हाइब्रिड मॉडल और भूमि खरीद या अधिग्रहण जैसे विकल्पों पर विचार की बात कही गई है।

भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में प्याज केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक उथलपुथल पैदा करने वाला अत्यंत संवेदनशील कारक है। जब भी प्याज के दाम आसमान पर पहुंचते हैं तो आम उपभोक्ता का बजट बिगड़ जाता है और जब कीमतें जमीन पर आ जाती हैं तो किसान बर्बाद हो जाता है।

यह समस्या किसी एक कारण से पैदा नहीं होती। प्राकृतिक मौसम, बाजार का असंतुलन, कमजोर भंडारण ढांचा, बिचौलियों की पकड़, विशेष रूप से केंद्र सरकार की अप्रत्याशित निर्यात नीतियां और नीतिगत समन्वय के अभाव का यह सामूहिक परिणाम है। वर्तमान में पैदा हुई प्याज की समस्या भी मोदी सरकार को इन विफल और पटरी से उतर चुकी नीतियों तथा कार्यप्रणाली का ही परिणाम है।

सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास रखने वाली भाजपा सरकार में सभी निर्णय दो-चार लोगों के हाथों में दे दिए गए हैं, लेकिन निचले स्तर पर जिस तरह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और पालिसी पैरालिसिस की स्थिति है, उसके परिणामस्वरूप देश के वह गरीब और जमीनी स्तर के लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार के कार्यकाल को मूल्यांकन करना अनिवार्य हो जाता है कि कहां नीतियां सफल रहीं और कहां प्रशासनिक तंत्र किसानों की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा। नितांतकत बात यह है कि सामान्य आदमी के लिए सरकार बनाने का दावा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार ने पिछले बारह वर्षों में आम लोगों को लाभ पहुंचाने वाला वास्तविक कोई काम नहीं किया है। जीएसटी लागू किया गया, जिसमें आम जनता ही पिस रही है। इसके अलावा नोटबंदी ने कहर बरपाया था। इसमें छोटे लोग ही पैसों के लिए परेशान होते और बैंकों के बाहर कतारों में खड़े होकर अपनी जात गंवाते दिखाई दिए।

कोरोना के दौरान अविवेकपूर्ण लॉकडाउन और उसके बाद अंधाधुंध टीकाकरण में भी आम और गरीब आदमी ही पिसा है। आयात और निर्यात की भी कोई ठोस नीति नहीं है, जिसके कारण किसानों और व्यापारियों सहै के ऊपर तलवार लटकी रहती है। इथेनॉल के नाम पर अजीब तरह का पेट्रोल और डीजल बेचकर अचानक ही गन्ने और मक्का की फसल पर आफत ला दी गई। इसके भंडारण के दौरान नुकसान हुआ, अब गन्ने की फसल में ही बीमारी लग गई है, जिससे उसकी उत्पादकता घट गई है। इसके परिणामस्वरूप जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई है। इसके कारण चीनी के दाम बढ़ गए और इथेनॉल के कारण लोगों को वहान खराब होने लगे। इस तरह सरकार की गैरजिम्मेदार नीतियों के कारण चीनी के दाम बढ़े हैं।

प्याज की भी ऐसी ही स्थिति कर का पेट्रोल और डीजल बेचकर अचानक ही गन्ने और मक्का की फसल पर आफत ला दी गई। इसके भंडारण के दौरान नुकसान हुआ, अब गन्ने की फसल में ही बीमारी लग गई है, जिससे उसकी उत्पादकता घट गई है। इसके परिणामस्वरूप जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई है। इसके कारण चीनी के दाम बढ़ गए और इथेनॉल के कारण लोगों को वहान खराब होने लगे। इस तरह सरकार की गैरजिम्मेदार नीतियों के कारण चीनी के दाम बढ़े हैं।

प्याज की भी ऐसी ही स्थिति कर का पेट्रोल और डीजल बेचकर अचानक ही गन्ने और मक्का की फसल पर आफत ला दी गई। इसके भंडारण के दौरान नुकसान हुआ, अब गन्ने की फसल में ही बीमारी लग गई है, जिससे उसकी उत्पादकता घट गई है। इसके परिणामस्वरूप जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई है। इसके कारण चीनी के दाम बढ़ गए और इथेनॉल के कारण लोगों को वहान खराब होने लगे। इस तरह सरकार की गैरजिम्मेदार नीतियों के कारण चीनी के दाम बढ़े हैं।

प्याज की भी ऐसी ही स्थिति कर का पेट्रोल और डीजल बेचकर अचानक ही गन्ने और मक्का की फसल पर आफत ला दी गई। इसके भंडारण के दौरान नुकसान हुआ, अब गन्ने की फसल में ही बीमारी लग गई है, जिससे उसकी उत्पादकता घट गई है। इसके परिणामस्वरूप जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई है। इसके कारण चीनी के दाम बढ़ गए और इथेनॉल के कारण लोगों को वहान खराब होने लगे। इस तरह सरकार की गैरजिम्मेदार नीतियों के कारण चीनी के दाम बढ़े हैं।

अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक 2026 लाकर इस पूरे गीत को राष्ट्रगान से साथ गाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही इसे रोकने को दंडनीय अपराध बना दिया है। यह बिल लोकसभा में 29 जुलाई को और राज्यसभा में 30 जुलाई को बिना चर्चा के पारित किया गया। राष्ट्रपति ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है। सवाल उठता है कि अगर यह विधेयक इतना ही जरूरी था तो सरकार अपने कार्यकाल के 12 वर्ष में इसे लेकर क्यों आई। और, अगर लाई तो संसद के दोनों सदनों में इस पर विस्तार से चर्चा करानी चाहिए थी। दूसरी तरफ विपक्ष खासकर कांग्रेस को इसे संसद में ही रोकने का प्रयास करना चाहिए था। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसमें किन्तु-परन्तु का क्या मतलब है।

दरअसल, आनेवाले दिनों में सात राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तरखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बीच पेपरलीक, बेरोजगारी और स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के खिलाफ छात्रों और युवाओं का बड़ा वर्ग आंदोलन कर रहा है। बढ़ती महंगाई से जनता बेजार है। सरकारी नौकरियों में अकेले केंद्र सरकार में 8 लाख से अधिक पद खाली हैं, जिसे भरने का सरकार की ओर से कोई रोडमैप नहीं दिखाई दे रहा है।

पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट से उद्धमी और आम लोग दुखी हैं। आगड़ी जाति के युवा आर्थिक आधार पर आरक्षण और यूजीसी के नए नियमन के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। अयोध्या के राममंदिर में चढ़ावा चोरी से सरकार की साख गिरी है, क्योंकि राममंदिर क्षेत्र तीर्थ द्रष्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने ही किया था। विपक्ष जनता के मुद्दों को हवा दे रहा है। ऐसे में समस्याओं से चोतरफा फिरी सरकार के समक्ष धार्मिक आधार पर विभाजन के सिवाय बचने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है।

प्याज संकट गहराया



स्नेहा सिंह

दी गई है। देश के गरीब लोग, जिनके नाम पर राजनीति की जाती है, उनकी थाली से प्याज भी गांवब होने लगा है। अच्छे दिन के नाम पर संवेदनशील सरकारें व्यापारियों, जनता और किसानों को बर्बाद किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्याज की कच्ची मौसम के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। भारत की कुल प्याज आपूर्ति में महाराष्ट्र, विशेष रूप से नासिक, लासलगांव और आसपास के जिले, रीढ़ की हड्डी जैसी भूमिका निभाते हैं। बुवाई के समय अत्यधिक बारिश या कटाई के समय होने वाली बेमौसम ओलावृष्टि नीतिगत समन्वय के अभाव का यह सामूहिक परिणाम है। वर्तमान में पैदा हुई प्याज की समस्या भी मोदी सरकार को इन विफल और पटरी से उतर चुकी नीतियों तथा कार्यप्रणाली का ही परिणाम है।

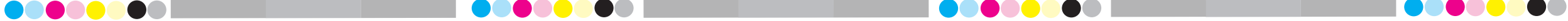
इसके अलावा मौसम की अनिश्चितता खेती के क्षेत्रफल, प्रति एकड़ उपज, फसल की भंडारण क्षमता और परिवहन व्यवस्था को सीधे प्रभावित करती है। जब आपूर्ति में 10-15 प्रतिशत की भी कमी आती है, तो बाजार में कृत्रिम या वास्तविक कमी पैदा हो जाती है और कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिलती है। वर्तमान में भी लगभग आठ प्रतिशत की कमी होने की बात सामने आ रही है।

दूसरी ओर, भारतीय कृषि बाजार प्याज के मामले में एक पारंपरिक दुष्चक्र में फंसा हुआ है। जब किसान को 2 से 5 रुपए प्रति किलो जैसे मामूली दाम मिलते हैं तो वह अगले सीजन में बुवाई कम कर देता है। परिणामस्वरूप कुछ महीनों बाद आपूर्ति घटने पर खुदरा बाजार में कीमत 70 से 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है।

ऊंचे भाव देखकर किसान फिर बड़े पैमाने पर बुवाई करता है, जिससे बाजार में अत्यधिक माल आने के कारण कीमतें फिर जमीन पर आ जाती हैं। यह समस्या केवल वर्तमान समय तक सीमित नहीं है, बल्कि एक दशक से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद भी सरकार इस चक्र को स्विच करने में विफल रही है, यह वास्तविकता है। प्याज ऐसी फसल है, जिसे उचित परिस्थितियों में महीनों तक संग्रहित किया जा सकता है, जिससे पूरे वर्ष धीरे-धीरे बाजार में इसकी आपूर्ति की जा सकती है। लेकिन भारत में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक वेयरहाउसिंग सुविधाओं का भारी अभाव है।

उचित वेंटिलेशन नहीं होने के कारण नमी, फंगस, अंकुरण और तापमान में बदलाव के कारण 25 से 35 प्रतिशत प्याज भंडारण के दौरान ही सड़ जाता है। भारत पूरे वर्ष पर्याप्त प्याज पैदा करता है, फिर भी भंडारण के अभाव में कुछ निश्चित महीनों में भारी कमी का सामना करना पड़ता है।

आधुनिक वैज्ञानिक भंडारण नेटवर्क नहीं होने के कारण जब बाजार में भाव गिरते हैं तो किसान डिस्ट्रेस सैलिंग यानी मजबूरी में कम कीमत पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर हो जाता है।



फेफड़ों में कैंसर से हर साल होती हैं लाखों मौतें

इस आदत को डॉक्टरों ने बताया सबसे नुकसानदायक

पूरे शरीर में ऑक्सीजन के संचार को ठीक बनाए रखने में फेफड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हालांकि समय के साथ इस अंग से संबंधित कई तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अध्ययनों में पाया गया है कि कई तरह की लाइफस्टाइल और पर्यावरणीय स्थितियां फेफड़ों को गंभीर रूप से क्षति पहुंचा रही हैं। यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर फेफड़ों में कैंसर के मामले भी बढ़ गए हैं।

फेफड़ों का कैंसर हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बन रहा है। ग्लोबोकेन 2022 के डेटा के अनुसार साल 2022 में दुनियाभर में फेफड़ों के कैंसर से लगभग 1.8 मिलियन (18 लाख) मौतें हुईं। ये दुनियाभर में कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण भी है। आश्चर्यजनक रूप से युवा आबादी में भी इस कैंसर के जोखिम बढ़ते हुए रिपोर्ट किए गए हैं।



फेफड़ों के कैंसर के गमले
भारत में भी फेफड़ों के कैंसर के केस बढ़ गए हैं। लंग्स कैंसर, भारत में सभी कैंसर का 5.9% और सभी तरह के कैंसर से संबंधित मौतों का 8.1% है। फेफड़ों में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण ये कैंसर होता है। कोशिकाओं के डीएनए में परिवर्तन की वजह से ऐसा होता है। कैंसर कोशिकाएं ट्यूमर बना सकती हैं। ट्यूमर के

कारण स्वस्थ ऊतकों को भी क्षति का जोखिम रहता है। समय के साथ कैंसर कोशिकाएं टूटकर शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकती हैं। अध्ययनों में फेफड़ों के कैंसर के लिए कई कारकों को जिम्मेदार पाया गया है जिसमें धूम्रपान सबसे प्रमुख है।

धूम्रपान सबसे बड़ा खतरा
धूम्रपान करने वाले लोगों में फेफड़ों के कैंसर का जोखिम सबसे ज्यादा होता है। सिगरेट की हर कश के साथ आपके लिए खतरा बढ़ता जाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि फेफड़ों के कैंसर से होने वाली 80% मौतें धूम्रपान से संबंधित हैं। इसके अलावा अगर आप धूम्रपान नहीं भी करते हैं पर सेकेडहैंड स्मोकिंग के शिकार हैं तो भी अपमें फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तम्बाकू उत्पादों के जलने से उत्पन्न धुएँ के संपर्क में आने को सेकेडहैंड स्मोकिंग कहा जाता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण, रसायनों के

अधिक संपर्क में रहना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है।

इसके लक्षणों की पहचान कैसे करें?
कैंसर आपके शरीर में लंबे समय तक यानी कई सालों तक बढ़ता रह सकता है, इससे पहले कि आपको इस बारे में पता चल सके। फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती चरणों में अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखते। हालांकि कुछ संकेत हैं जिनपर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

फेफड़ों में और उसके आस-पास होने वाले कैंसर के कारण आपको लंबे समय तक खांसी होती रह सकती है। इसके अलावा खांसी के साथ खून आने, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट होने जैसे समस्याएं कैंसर का संकेत हो सकती हैं। इन लक्षणों के साथ हड्डी में दर्द, बिना प्रयास किए वजन कम होने, भूख न लगने या चेहरे-गर्दन में सूजन की दिक्कत हो तो सावधान हो जाएं।

फेफड़ों के कैंसर से कैसे बचें?
फेफड़ों के कैंसर को रोकने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन कुछ उपायों की मदद से आप अपने जोखिमों को कम कर सकते हैं। इसके लिए धूम्रपान से दूरी बनाना सबसे जरूरी है। रसायनों और प्रदूषण वाले स्थानों से भी बचें। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम की आदत फेफड़ों के साथ कई अन्य कैंसर के खतरे से भी आपको बचा सकती है।

डेस्क जॉब करने वाले संभल जाएं

घंटों बैठे रहना बना सकता है दिल को बीमार!



आज के समय में ऑफिस का काम हो या घर से वर्क फ्रॉम होम, ज्यादातर लोगों का काफी समय कुर्सी पर बैठकर ही गुजरता है। कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने लगातार कई घंटे बैठे रहना अब सामान्य दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना आपके दिल की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है?

ऐसे में खासकर ऐसे लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, जो रोजाना 8 से 10 घंटे या उससे ज्यादा समय तक डेस्क पर बैठकर काम करते हैं। आइए जानते हैं लंबे समय तक बैठने से दिल पर क्या असर पड़ सकता है और इससे बचने के आसान तरीके क्या हैं।

लंबे समय तक बैठे रहने से दिल पर क्या असर पड़ता है?

लगातार कई घंटे बैठे रहने से शरीर की शारीरिक गतिविधि काफी कम हो जाती है। इसका असर धीरे-धीरे पूरे शरीर पर पड़ सकता है। लंबे समय तक निर्भ्रक्य रहने से वजन बढ़ने, ब्लड प्रेशर बढ़ने और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में परेशानी जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। ये सभी स्थितियां आगे चलकर दिल की सेहत को प्रभावित कर सकती हैं।

बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का खतरा

जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं और शारीरिक गतिविधि बहुत कम करते हैं, उनमें हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। लगातार बैठे रहने की आदत शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और वजन जैसे हार्ट रिस्क फैक्टरों को प्रभावित कर सकती है।

असर
एक ही जगह लंबे समय तक बैठे रहने से पैरों और शरीर के निचले हिस्से में ब्लड फ्लो कम हो सकता है। लंबे समय तक निर्भ्रक्य रहने के कारण पैरों में भारीपन, अकड़न या सूजन जैसी परेशानी भी महसूस हो सकती है।

वजन बढ़ने का खतरा
लंबे समय तक बैठकर काम करने से शरीर कम कैलोरी खर्च करता है। अगर खान-पान भी सही नहीं है, तो वजन बढ़ सकता है। अधिक वजन और मोटापा दिल की बीमारियों के प्रमुख

समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

ऑफिस में काम करने वाले लोग कैसे बचें?
अगर आपका काम घंटों बैठकर करने वाला है, तो कुछ छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर शरीर को एक्टिव रखा जा सकता है। हर 30 से 60 मिनट में कुछ देर के लिए कुर्सी से उठें ऑफिस में संभव हो तो थोड़ी देर पैदल चलें फोन पर बात करते समय खड़े होने या चलने की कोशिश करें लंच के बाद कुछ मिनट वॉक



जोखिम कारकों में शामिल हैं।

ब्लड प्रेशर और शुगर पर असर
शारीरिक गतिविधि की कमी से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना मुश्किल हो सकता है। लंबे समय तक बैठे रहने के साथ अगर रोजाना एक्सरसाइज भी न की जाए तो मेटाबॉलिक

करें लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें वॉक, योग या एक्सरसाइज के लिए समय निकालें काम के बीच पैरों और शरीर को स्ट्रेच करते रहें

घर पर इस आसान विधि से बनाएं काजू कतली

त्योहारों का सीजन कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है। ऐसे में बाजारों में इसकी धूम दिखाई देने लगी है। लोग खरीदारी से लेकर घर की साफ-सफाई में भी लग गए हैं। जब भी कोई त्योहार आता है, तो सबसे ज्यादा भीड़ मिठाईयों की दुकान पर देखने को मिलती है, क्योंकि त्योहारों पर लोग एक-दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं।



काजू कतली बनाने का सामान

काजू — 1 कप (200 ग्राम)
चीनी — 1/2 कप (100 ग्राम)
पानी — 1/4 कप
चांदी का वर्क

विधि
काजू कतली बनाना काफी आसान है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको काजू का पाउडर तैयार करना है। काजू पाउडर बनाने के लिए पहले इसे अच्छी तरह से सुखा लें। सुखाने के बाद काजू को महीन पीस लें।

इसे पूरी तरह से नहीं पीसें, वरना ये तेल छोड़ देगा। अब इसे साइड में रखकर एक कढ़ाई में 1/2 कप चीनी और 1/4 कप पानी डालकर धीमी आंच पर चीनी घुलने तक मिक्स करें। चीनी पूरी तरह घुलने पर इसे थोड़ा और पकाएं ताकि यह एक तार की चाशनी बन जाए। चाशनी तैयार होने के बाद इसमें काजू का मिश्रण डालें। ध्यान रखें इसे आपको लगातार चलाना है, वरना ये जलने लगेगा। इसे तब तक पकाएं जब तक यह कढ़ाई के किनारों से अलग न होने लगे। जब इसका सही का पेस्ट तैयार हो जाए तो गैस बंद करके इसे थोड़ा ठंडा होने दें। जब ये छूने लायक ठंडा हो जाए तो इसे हाथ से हल्का गुंथ लें। अब एक चिकनी सतह वाली ट्रे पर धी लगाकर मिश्रण को फैला दें। अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसे डायमंड शेप में काट लें। आखिर में इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं। तो बस आपकी काजू कतली तैयार है। त्योहारों के सीजन में इसका लुफ्त उठाएं।

अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप बहुत कम खाते हैं, फिर भी वजन लगातार बढ़ रहा है, तो सिर्फ प्लेट में रखी रोटियों की संख्या देखकर पूरी तस्वीर समझना मुश्किल है। वजन बढ़ने के पीछे आपकी पूरी दिनचर्या समेत कई कारण हो सकते हैं। यहां हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि वजन कम करने के लिए सिर्फ रोटियों की संख्या कम करना काफी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए आइए जानते हैं।

सिर्फ 2 रोटी खाने पर भी वजन क्यों बढ़ सकता है?

कई लोगों को लगता है कि उन्होंने सिर्फ दो रोटी खाई हैं, इसलिए उनका खाना कम है। लेकिन रोटी के साथ सब्जी में कितना तेल, दाल में कितना घी, दही, अचार, मिठाई या दूसरी चीजें ली गईं, यह भी वजन पर असर डालता है। वजन बढ़ने या



घटने में पूरे दिन में ली गई कुल कैलोरी और शरीर द्वारा खर्च की गई कैलोरी महत्वपूर्ण होती है।

चाय-बिस्किट और छोटे स्नैक्स
सुबह की चाय में चीनी, ऑफिस में बिस्किट, शाम की

नमकीन, जूस या सॉफ्ट ड्रिंक जैसी चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन बार-बार लेने से दिनभर की कुल कैलोरी काफी बढ़ सकती है। इसलिए वजन बढ़ने पर कुछ दिनों तक अपनी पूरी डाइट नोट

करके देखना फायदेमंद हो सकता है।

दिनभर बैठे रहना
अगर आप कम खाते हैं लेकिन दिनभर ज्यादातर समय बैठे रहते हैं और शारीरिक गतिविधि बहुत कम है, तो शरीर की रोजाना कैलोरी खर्च भी कम हो सकती है। ऑफिस वर्क, लंबे समय तक मोबाइल या टीवी देखना और रोजाना कम चलना वजन बढ़ने की समस्या को बढ़ा सकता है।

नींद पूरी न होना
लगातार कम नींद लेने से भूख और पेट भरे होने का एहसास कराने वाले हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं। इसके कारण कुछ लोगों को ज्यादा खाने की इच्छा होती है और मीठे या हाई-कैलोरी फूड की क्रेविंग बढ़ सकती है। इसलिए वजन कम करने के लिए डाइट के साथ पर्याप्त नींद भी जरूरी है।

ज्यादा तनाव लेना
लगातार तनाव रहने पर कुछ लोगों में ज्यादा खाने की आदत विकसित हो सकती है। तनाव के

दौरान मीठा, तला-भुना या जंक फूड खाने की इच्छा बढ़ सकती है। अगर आप तनाव में बार-बार कुछ खाते हैं, तो इसका असर वजन पर दिखाई दे सकता है।

थायरॉयड की समस्या

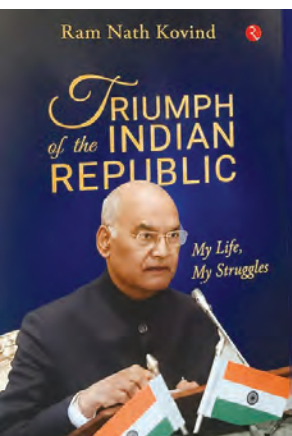
अगर वजन बढ़ने के साथ लगातार थकान, ठंड ज्यादा लगना, कब्ज, त्वचा का रूखा होना या बाल झड़ने जैसी समस्याएं भी हैं, तो थायरॉयड की जांच के लिए डॉक्टर से सलाह ली जा सकती है। थायरॉयड की समस्या में शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो सकता है।

कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

अगर आपका वजन लगातार बिना किसी स्पष्ट कारण के बढ़ रहा है या इसके साथ अत्यधिक थकान, सूजन, सांस फूलना, कब्ज, ठंड ज्यादा लगना या दूसरे असामान्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।

संघर्ष को साधना में बदलने की कहानी

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पुस्तक 'Triumph of the Indian Republic: My Life, My Struggle' का विज्ञान भवन, नई दिल्ली में विमोचन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी की मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति ने इसे विशेष गरिमा प्रदान की। पुस्तक के विमोचन अवसर पर व्यक्ति विचारों ने भी इसकी मूल भावना को रेखांकित किया—यह केवल एक व्यक्ति की आत्मकथा नहीं, बल्कि संघर्ष, संकल्प, ईमानदारी, विनम्रता और लोकसेवा के मूल्यों की यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद की साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की यात्रा को असाधारण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन परिश्रम, ईमानदारी, समर्पण और जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। खासतौर पर पांच वर्ष की उम्र में मां को खो देने के बाद पिता द्वारा



मां और पिता दोनों की भूमिका निभाने का प्रसंग इस जीवन-कथा को भावनात्मक गहराई देता है। प्रधानमंत्री के अनुसार यह पुस्तक गरीब और वंचित युवाओं के लिए प्रेरणा तथा मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती है। पुस्तक की खासियत यह है कि इसमें रामनाथ कोविंद ने अपने जीवन के संघर्षों को किसी औपचारिक उपलब्धियों की सूची की तरह नहीं, बल्कि अनुभवों और संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत किया है। मां के निधन के बाद का

खालीपन, रिश्तेदार चाची से मिला अपनापन, पिता का संघर्ष, बहन के घर रहकर पढ़ाई, बीएनएसडी इंटर कॉलेज में प्रवेश, शिक्षकों और मित्रों से मिले संस्कार तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्राप्त प्रेरणाओं का उल्लेख उनके व्यक्तित्व के निर्माण की कहानी को सामने लाता है।

300 से अधिक पृष्ठों की यह पुस्तक छात्र जीवन से आगे बढ़कर उनके व्यावसायिक और सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों को भी दर्ज करती है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्ति, सविता कोविंद से विवाह, यूपीएससी में चयन के बावजूद नौकरी न करने और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत को अपनाने का निर्णय उनके लक्ष्य-केंद्रित व्यक्तित्व को सामने लाता है। आगे चलकर राज्यपाल और राष्ट्रपति के रूप में निभाई गई जिम्मेदारियों का क्रमबद्ध विवरण पुस्तक को और महत्वपूर्ण बनाता

है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुस्तक को युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए रामनाथ कोविंद जैसे व्यक्तित्व की यात्रा को दुर्लभ उपलब्धि माना। स्वयं कोविंद का संदेश भी पुस्तक की आत्मा है—विचारों की सकारात्मकता और देश के प्रति समर्पण व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। उनका जीवन बताता है कि बड़े सपने देखना पर्याप्त नहीं; उन्हें पूरा करने के लिए उतनी ही बड़ी जगहन, ईमानदारी और दृढ़ता चाहिए। इस दृष्टि से 'Triumph of the Indian Republic' एक ऐसे सामान्य व्यक्ति की असाधारण यात्रा है, जिसने कठिनाइयों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। यह पुस्तक बताती है कि परिस्थितियां रास्ता कठिन कर सकती हैं, लेकिन लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास, परिश्रम और चरित्र की दृढ़ता तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। अलग-अलग जगहों और परिवारों में इसके डिजाइन और पहनने का

समीक्षक -पुरुषोत्तम भटोरिया

भाभी की कलाई पर क्यों बांधी जाती है लुंबा राखी?

इसके पीछे की खास परंपरा और वजह

रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्रेम और आपसी स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। कई परिवारों में भाई के साथ ही भाभी को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन पर भाभी के लिए भी एक खास तरह की राखी लाई जाती है, जिसे लुंबा राखी कहा जाता है। यह सामान्य राखी से अलग होती है और इसे खास तौर पर भाभी के लिए डिजाइन किया जाता है।

वया होती है लुंबा राखी?
लुंबा राखी का डिजाइन आमतौर पर ऐसा होता है कि इसे कलाई पर बांधने के बजाय चूड़ियों या कंगन के साथ सजाया जा सके। इसमें मोतियों, लटकन, कुंदन, धागे और अन्य सजावटी तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। अलग-अलग जगहों और परिवारों में इसके डिजाइन और पहनने का



तरीका अलग हो सकता है।

भाभी को क्यों बांधते हैं लुंबा राखी?
कई पारिवारिक और क्षेत्रीय परंपराओं में भाभी को परिवार का अहम हिस्सा मानते हुए रक्षाबंधन की खुशी में उन्हें भी शामिल किया जाता है। ननद द्वारा भाभी को लुंबा

हैं।

लुंबा राखी का क्या है महत्व?
इसका महत्व मुख्य रूप से पारिवारिक परंपरा, स्नेह और रिश्तों की खूबसूरती से जुड़ा है। लुंबा राखी के जरिए भाभी को त्योहार की खुशियों में शामिल करने और ननद-भाभी के रिश्ते में प्रेम व अपनापन व्यक्त करने का भाव दिखाई देता है।

वया हर जगह बांधी जाती है लुंबा राखी?
हालांकि लुंबा राखी बांधने की परंपरा पूरे भारत में एक जैसी नहीं है। यह खास तौर पर कुछ समुदायों और परिवारों में अधिक प्रचलित है। इसलिए इसे रक्षाबंधन की अनिवार्य रस्म के बजाय क्षेत्रीय और पारिवारिक परंपरा के रूप में समझना बेहतर है। इस तरह लुंबा राखी रक्षाबंधन के पारंपरिक भाई-बहन के रिश्ते के साथ परिवार के अन्य रिश्तों में स्नेह और अपनापन जोड़ने वाली खूबसूरत परंपरा है।

राहुल गांधी इस सरकार से कुछ भी करा सकते हैं

आदिवासी छात्रों की हड़ताल खत्म होने पर बोले पवन खेड़ा



राहुल गांधी के पुराने बयान को दोहराते हुए पवन खेड़ा

नई दिल्ली, 26 अगस्त (एजेंसियां)। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के उठाए मुद्दों पर सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसका श्रेय लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जाता है। पवन खेड़ा का यह बयान ऐसे समय आया है, जब राहुल गांधी के महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने हॉस्टलों में आदिवासी छात्रों के लिए उम्र की सीमा खत्म कर दी है। राहुल गांधी ने 24 अगस्त को

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उन छात्रों की समस्या के बारे में बताया था, जो पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। पवन खेड़ा ने इस पर कहा कि राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वह इस सरकार से कुछ भी कहलवा सकते हैं। लगता है कि अब हम उससे आगे बढ़ गए हैं। वह उनसे कुछ भी करवा सकते हैं।

कांग्रेस से राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने आगे कहा कि गांधी के असर की वजह से पूर्व शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, संसद

पुलिस स्टेशन में उनके विरोध प्रदर्शन के कारण साहिल लोचब के मामले में एफआईआर दर्ज हुई और अब महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों की मांगें सुनी हैं। उन्होंने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। खेड़ा ने आगे लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, साहिल लोचब के मामले में एफआईआर और अब महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों की मांगें, यह तो बस शुरुआत है। आगे-आगे देखिए क्या होता है।

बता दें कि पुणे में छात्रों के 13 दिन के विरोध-प्रदर्शन के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को आदिवासी हॉस्टलों में एडमिशन के लिए 30 साल की उम्र सीमा हटा दी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भूख हड़ताल कर रहे आदिवासी छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहा था। राहुल गांधी ने फडणवीस को लिखे एक पत्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से

आदिवासी छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मिलने और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया था।

कर्नल सौफिया कुरैशी मामला: मंत्री विजय शाह पर एक्शन की मंजूरी नहीं

भोपाल, 26 अगस्त (एजेंसियां)। कांग्रेस ने बुधवार को मांग की है कि कर्नल सौफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी नहीं देने पर मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार को राष्ट्रपति बर्खास्त करें।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि सरकार एक बड़बोले मंत्री को राजनीतिक संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल एक राजनीतिक व्यक्ति को जवाबदेही से बचाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में मध्यप्रदेश सरकार को विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी पर दो सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया था। हालांकि, मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में कोई प्रस्ताव चर्चा

भट्टी ने सिंगरेणी को महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में विस्तार का निर्देश दिया

सिंगरेणी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक



हैदराबाद, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने तेलंगाना की सांख्यिक क्षेत्र की जीवनरेखा मानी जाने वाली सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को लाभदायक और मजबूत संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है, ताकि इसे आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त संस्था के रूप में सौंपा जा सके। बुधवार को हैदराबाद के महात्मा ज्योतिराव फुले प्रज्ञा भवन में सिंगरेणी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक में भट्टी विक्रमार्क ने अधिकारियों को कोयला खनन से आगे बढ़कर विशेष रूप से महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के क्षेत्र में खनन के अवसर तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों और कोयला खनन के सभी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय नीलामी कार्यक्रमों में सिंगरेनी को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। बैठक में सिंगरेणी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. बुद्धप्रकाश ज्योति, निदेशक सूर्यनारायण, वेंकटेश्वरु और तिरुमला राव

समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एल नीनो के प्रभाव के कारण बिजली की मांग बढ़ने की पृष्ठभूमि में उपमुख्यमंत्री ने सिंगरेनी के कोयले की बढ़ती मांग के अनुरूप कोयला उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सिंगरेनी को केवल कोयला खनन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे खनन क्षेत्र में अपने संचालन का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य की जनता की सरकार इसके लिए आवश्यक हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। भट्टी विक्रमार्क ने बताया कि आने वाले समय में वेनेडियम और टाइटेनियम वाले खनिज ब्लॉकों की नीलामी होने की संभावना है। उन्होंने अधिकारियों को इन खनिज ब्लॉकों को हासिल करने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।

राज्य में गंभीर सूखे की स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि सिंगरेनी को तेलंगाना की ऊर्जा सुरक्षा में अपने योगदान को और मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक घटनाक्रमों के अनुरूप सरकार सिंगरेनी को तांबा, ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े खनन अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और चिली समेत विभिन्न देशों में खनन एवं निवेश के अवसरों का अध्ययन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों की सेवाएं ली गई हैं। इसका उद्देश्य सिंगरेनी के विकास और विविधीकरण के लिए नए अवसर तलाशना है।

भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कार्यबल तैयार करने उद्योग जगत के साथ साझेदारी जरूरी : श्रीधर बाबू

हैदराबाद, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री दहिला श्रीधर बाबू ने राज्य में कौशल विकास की व्यवस्था को मजबूत करने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कार्यबल तैयार करने के लिए उद्योगों तथा उद्यमियों से राज्य सरकार के साथ साझेदारी करने का आह्वान किया है। बुधवार को बंजारा हिल्स स्थित एक होटल में बोइंग, लॉर्निंग लिंक्स फाउंडेशन और केंद्रीय औजार डिजाइन संस्थान की ओर से आयोजित प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम में श्रीधर बाबू ने कहा कि सरकार तेलंगाना के युवाओं को उद्योग की बदलती जरूरतों और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप कौशल प्रदान करने के लिए काम कर रही है। मंत्री ने बोइंग कौशल विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले युवाओं, दिव्यांगजनों और पूर्व सैनिकों को प्रमाणपत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल भी लगातार बदल रहे हैं। युवाओं को इन बदलावों के लिए तैयार करने के लिए सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। श्रीधर बाबू ने कहा

मिलाद-उन-नबी कार्यक्रम में शामिल हुए महेश कुमार गौड़

पैगंबर मोहम्मद के शांति, भाईचारे के संदेश को बताया समाज के लिए आदर्श



निजामाबाद, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। निजामाबाद शहर के किला रोड के पास आयोजित मिलाद-उन-नबी कार्यक्रम में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य महेश कुमार गौड़ ने भाग लिया।

करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने तेलंगाना में सभी वर्गों के लोगों के सुख-शांति और भाईचारे के साथ रहने की कामना की। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि धार्मिक सद्भाव, एक-दूसरे के प्रति सम्मान और सामाजिक एकता को मजबूत करने से ही समाज का समग्र विकास संभव है। उन्होंने कहा कि मिलाद-उन-नबी जैसे अवसर लोगों को शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देते हैं तथा समाज में आपसी विश्वास को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में स्थानीय कांग्रेस नेताओं, जनप्रतिनिधियों, मुस्लिम धर्मगुरुओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।

एक्साइज सीआई और कॉन्स्टेबल पर विभागीय कार्रवाई

कोतागुडेम, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। जिले के भद्राचलम एक्साइज पुलिस स्टेशन में गांजा केस में गिरफ्तार दो लोगों से जुड़े पंचनामा और केस के अन्य रिकॉर्ड्स में कथित तौर पर बदलाव और जालसाजी करने के लिए एक प्रोहिबिशन और एक्साइज इंस्पेक्टर और एक कॉन्स्टेबल पर कार्रवाई की गई।

बताया गया कि एक्साइज एनफोर्समेंट टीम ने 4 अगस्त को ओडिशा से दो गांजा तस्करी को पकड़ा और उन्हें भद्राचलम एक्साइज पुलिस स्टेशन को सौंप दिया।

आरोपियों को उसी दिन कोर्ट में पेश किया जाना था और न्यायिक हिरासत में भेजा जाना था। लेकिन, लापरवाही बरतते हुए, एक्साइज इंस्पेक्टर ने दोनों आरोपियों की निगरानी के लिए एक कॉन्स्टेबल को तैनात किया और उन्हें रात भर स्टेशन पर ही रखा। मौका पाकर, आरोपियों में से एक, माधबा हंतल, 5 अगस्त की सुबह स्टेशन से भाग गया।

इस घटना से घबराकर, एक्साइज सीआई ने मामले की जानकारी एक्साइज सुपरिंटेंडेंट को दी। इसके बाद, सीआई ने एनफोर्समेंट अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर करके पंचनामा रिपोर्ट में बदलाव किया

ताकि यह गलत तरीके से दिखाया जा सके कि दो लोगों के बजाय केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, और अकेले उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करके कोर्ट को गुमराह किया।

जब एनफोर्समेंट अधिकारियों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत की। प्रोहिबिशन और एक्साइज कमिश्नर, सी हरि किरण ने 24 अगस्त के एक मेमो में एक्साइज सीआई, शेख रहीमुनिसा बेगम और कॉन्स्टेबल सीएच रवि कुमार को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया।

इसके अलावा, एक्साइज सुपरिंटेंडेंट ए शीनिवास रेड्डी, जिन्होंने कथित तौर पर सीआई रहीमुनिसा बेगम की मदद की थी, उन्हें अटैचमेंट (पद से हटाकर दूसरी जगह संबद्ध) में डाल दिया गया और इन-चोर्ज एक्साइज सुपरिंटेंडेंट की जिम्मेदारी एस जनेया को सौंप दी गई, जो पहले कोतागुडेम में काम करते थे। दहिला और, जिले के आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। रिहायशी इलाकों में अवैध शराब की दुकानों (बेट शॉप्स) से होने वाली समस्याओं के बारे में कई शिकायतें मिलने के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी।

कार चोरी का आरोपी गिरफ्तार, 8.90 लाख की संपत्ति बरामद

हैदराबाद, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। अद्वार पुलिस ने चार पहिया वाहन और अन्य सामान चोरी करने के मामले को खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की हुईई आई-20 कार को लैपटॉप समेत 8.90 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान सैयद मजहर उर्फ शटर उर्फ टकला उर्फ मजहर खान, उम्र 30 वर्ष, निवासी उपपरपल्ली, राजेंद्रनगर, रंगारेड्डी जिला के रूप में हुई है। आरोपी मूल रूप से मुल्तान नगर, रंगारेड्डी जिला का रहने वाला है और फिलहाल बेरोजगार था। यह कार्रवाई अद्वारु थाने में दर्ज अपराध संख्या 925/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता का धारा 305(बी) के मामले में की गई। पुलिस ने आरोपी को 22 अगस्त को हुई वाहन चोरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 22 अगस्त की रात करीब 11.30 बजे पिस्ता हाउस, अद्वारु में पिलर नंबर 169 के पास स्थित वॉलेट पार्किंग से हुईई आई-20 एस्टा कार चोरी हुई थी। शिकायतकर्ता अपने रिश्तेदार के साथ भोजन करने पिस्ता हाउस पहुंचे थे और उन्होंने अपनी कार संख्या टीजी07 एडी2657 वॉलेट पार्किंग कर्मचारियों को सौंप दी थी। इसी दौरान



आरोपी पिस्ता हाउस पहुंचा और उसने देखा कि वॉलेट कर्मचारी ग्राहकों की कारों की चाबियां लेकर वाहनों को पार्क कर रहे थे तथा सभी चाबियां वॉलेट काउंटर के पास रखी जा रही थीं। कर्मचारियों की व्यस्तता का फायदा उठाकर आरोपी ने काउंटर से दो कारों की चाबियां चुरा लीं और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद उसने एक चाबी दबाकर यह पता लगाया कि कौन-सी कार उससे जुड़ी है। चाबी दबाने पर पिस्ता हाउस के पास बंसाली मार्बल दुकान के निकट खड़ी स्टारी नाइट रंग की हुईई आई-20 की लाइट जल उठी। आरोपी ने आसपास देखा और किसी को मौजूद नहीं पाकर कार में प्रवेश किया, उसे स्टार्ट किया और वहां से फरार हो गया। दूसरी चुराई गई चाबी उसने बंसाली मार्बल दुकान के पास फेंक दी। पुलिस के अनुसार आरोपी आदतन अपराधी है और पहले भी संपत्ति

तथा गंभीर अपराधों में शामिल रहा है। वह कई बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। बेरोजगार होने के कारण वह बिना काम के घूम रहा था। मिलाद-उन-नबी त्योहार के महेंजर आरोपी अपने पैतृक गांव हिलातपुर, हलिखेड तालुक, बीदर जिला, कर्नाटक जाना चाहता था। वहां नासिर शाह दरगाह के निकट कस्बिस्तान में उसके पिता की कब्र है। लंबी यात्रा के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसलिए उसने चार पहिया वाहन चोरी कर उससे भागने की योजना बनाई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से स्टारी नाइट रंग की हुईई आई-20 एस्टा कार और एक लैपटॉप बरामद किया। बरामद संपत्ति का कुल मूल्य 8.90 लाख रुपये बताया गया है। चोरी गई संपत्ति में 11 ग्राम वजन की दो सोने की अंगुठियां भी शामिल थीं। कुल चोरी गई संपत्ति का मूल्य करीब 9 लाख रुपये था। आरोपी के पास से एक ओपपो मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। यह कार्रवाई राजेंद्रनगर जोन के पुलिस उपायुक्त एस. शीनिवास, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के. एस. राव, राजेंद्रनगर संभाग के सहायक पुलिस आयुक्त टी. शीनिवास तथा अद्वारु थाना प्रभारी ए. सीतैया की निगरानी में की गई।

दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय में क्षेत्रीय हिंदी नाटक प्रतियोगिता संपन्न

‘अंतिम पत्र’ को प्रथम, ‘पितृ स्नेह’ को द्वितीय और ‘ओटीपी’ को तृतीय पुरस्कार



हैदराबाद, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय में 24 और 25 अगस्त को क्षेत्रीय हिंदी नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बुधवार को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव मुख्य अतिथि तथा अपर महाप्रबंधक सत्यप्रकाश विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, राजेश पी. खांडे ने की। इस अवसर पर मुख्यालय के प्रमुख विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्षों के अलावा सिकंदराबाद तथा हैदराबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक भी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में दक्षिण मध्य रेलवे के प्रधान कार्यालय, सिकंदराबाद मंडल, हैदराबाद मंडल, नांदेड मंडल और लालगुडा कारखाना की टीमों ने अपने-अपने नाटकों का मंचन

किया। सिकंदराबाद मंडल द्वारा प्रस्तुत ‘अंतिम पत्र’ को प्रथम पुरस्कार मिला। प्रधान कार्यालय द्वारा प्रस्तुत ‘पितृ स्नेह’ ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि लालगुडा कारखाना के ‘ओटीपी’ को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

हैदराबाद मंडल के ‘रील से रियल तक’ तथा नांदेड मंडल के ‘पट्टी की शेरनी’ को प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अभिनेता, संगीत, रूप सजा सहित विभिन्न श्रेणियों में भी पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में डॉ. राममोहन होलागुंडी तथा प्रो. करण सिंह उत्तल को आमंत्रित किया गया था। डॉ. राममोहन होलागुंडी निरुभिता के स्कूल ऑफ ड्रामा, हैदराबाद के संस्थापक-निदेशक हैं। वे रंगकर्मी, निर्देशक, रंगमंच शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेता के रूप में भी सक्रिय हैं। प्रो. करण सिंह उत्तल मोलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय,

गच्चीबावली, हैदराबाद के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। उन्हें हिंदी कथा साहित्य के नाट्य रूपांतरण, नाटक, फिल्म एवं मीडिया, शोध-प्रविधि, लोक साहित्य तथा साहित्य के फिल्ममार्तण जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है। क्षेत्रीय हिंदी नाटक प्रतियोगिता का आयोजन दक्षिण मध्य रेलवे के उप महाप्रबंधक (राजभाषा) एम.के. नारायण के नेतृत्व में किया गया। प्रतियोगिता के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों ने हिंदी रंगमंच के प्रति अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और प्रतिबद्धता का प्रभावी प्रदर्शन किया।

स्वतंत्र वार्ता

Email :
svaarthta2006@gmail.com
svaarthta@rediffmail.com
svaarthta2006@yahoo.com

Epaper :
epaper.swatantravarta.com

For Advertisement :
swadds1@gmail.com

तेल पाम की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगी तेलंगाना सरकार

हैदराबाद, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। तेलंगाना सरकार पानी की अधिक खपत वाली धान की खेती पर राज्य की अत्यधिक निरभराता कम करने के उद्देश्य से तेल पाम की खेती का बड़े पैमाने पर विस्तार करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही तेल पाम के प्रसंस्करण और इससे जुड़े अन्य उद्योगों में निवेश को भी बढ़ावा

कांग्रेस में तेलंगाना नेतृत्व को दबाने का प्रयास : राजगोपाल रेड्डी

हैदराबाद, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। मुन्नागोडे के विधायक कोमटरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस में तेलंगाना नेतृत्व को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क के साथ हाल में हुई अपनी मुलाकात को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि बैठक में केवल मुन्नागोडे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि से संबंधित विषय पर चर्चा हुई थी। इसका मंत्री कांडा सुरेखा की बेटी कांडा सुस्मिता पटेल की टिप्पणियों से कोई संबंध नहीं था। पत्रकारों से बातचीत में राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री रवंत रेड्डी की आलोचना नहीं की

लिया था, आज महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांडा सुस्मिता पटेल से संबंधित मामले पर कांग्रेस की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेट्री की अनुशासन समिति फैसला करेगी।

पश्चिम बंगाल में सुरक्षित मिले सात लापता मछुआरे

अमरावती, 26 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। आंध्र प्रदेश के मंत्री किंरापु अच्चायडु ने बुधवार को कहा कि कोनासीमा जिले से समुद्र में जाने के बाद लापता हुए सात मछुआरे पश्चिम बंगाल में सुरक्षित मिल गए हैं। अल्लारामपु मंडल के ओडलारेवु, डुम्लालपेटा और वसालाथिप्पा गांवों के ये सात मछुआरे 3 अगस्त को मुबह करीब 10 बजे मछली पकड़ने के लिए ओडलारेवु फिश लैंडिंग सेंटर से निकले थे। ये उस दिन सुबह करीब 11 बजे तक अपने परिवारों के संपर्क में थे, जिसके बाद संपर्क टूट गया। नाव के 12 अगस्त तक लौटने की उम्मीद थी, लेकिन वह नहीं लौटी, जिसके बाद अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू किया।। कृषि और मत्स्य पालन मंत्री ने एक प्रेस वार्ता में कहा, कोनासीमा जिले के ओडलारेवु से समुद्र में जाने के बाद लापता हुए सात मछुआरे पश्चिम बंगाल में सुरक्षित पाए गए हैं, जिससे उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि नाव शंकरपुर फिशिंग हार्बर के पास मिली और उस पर सवार सभी सात मछुआरे सुरक्षित पाए गए। अच्चायडु ने कहा कि मछुआरे स्वस्थ हैं और उन्हें अपने परिवारों से बात करने की अनुमति दी गई है।



केबीआर पार्क में इच्छापूर्ति गणेशजी की पूजा में राजेंद्र कुमार अग्रवाल सुरेंद्र कुमार अग्रवाल गोपाल बलदा विठ्ठलदास अग्रवाल बड़े गांव वाले प्रमोद कुमार, दीपक कुमार सत्यवाला अशोक कुमार लाखोटिया अजय अग्रवाल भारत भूषण सेसैया, डॉ गिरजा किशोर गुप्ता, सुभाष अग्रवाल सुरेंद्र मोहन, सुरेश अग्रवाल सीए विजय कुमार अग्रवाल, विनोद टिकमानी शीनिवास वेंकटेश्वर राव विजय लक्ष्मी विजय लक्ष्मी रेड्डी एवं अन्य।

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या सं.108 से 113 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: हैदराबाद डिवीजन: अरिआपुर/एससी पर दामता का विस्तार & इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का उन्नयन। अनुमानित मूल्य ₹ 3,39,68,484.00, अग्रधन ₹ 6,79,400.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 109 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: एस&ई स्टोर्स सहित कर्मचारी बाउंड्री वाल का पुर्ननिर्माण के साथ एस&ई स्टोर्स में निर्दिष्ट स्थान पर आएसपीटी स्टोर्स का निर्माण। अनुमानित मूल्य ₹ 8,41,32,196.00, अग्रधन ₹ 1,66,82,700.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 110 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: हैदराबाद डिवीजन: निम्न एससीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर की रीकंस्ट्रक्शन (एल&टी, अडवानी ओलॉकान, डिम्पनपुर, शार्प-650 मे के टर्न, सी-1-194-इन्वेस्टिड का उन्नयन करने हेतु पाइपर्स&क्रॉसिंग स्लीपर्स की संबंधित रीकंस्ट्रक्शन अथवा काट आयरन स्लीपर्स की रीकंस्ट्रक्शन हेतु आरडीएसओ द्वारा तत्समान अनुमोदन) (पाइपर्स & क्रॉसिंग्स कार्यों की पारट रीकंस्ट्रक्शन)। अनुमानित मूल्य ₹ 6,66,57,250.00, अग्रधन ₹ 1,33,200.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 111 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: वर्ष 2026-27 के लिए एचवावली डिवीजन में पुलों के कार्यों का डिजाईन हेतु वास्तविक सेवा ठेका। अनुमानित मूल्य ₹ 60,00,000.00, अग्रधन ₹ 1,20,000.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 112 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: सीडब्ल्यूएस/एलजीडीएस पर नई एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की तरफ टैक्सर-1 (22X10.5एम) & टैक्सर-11 (साइज 22X7एम) का विस्तार। अनुमानित मूल्य ₹ 7,11,12,718.00, अग्रधन ₹ 1,42,300.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 113 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: सीडब्ल्यूएस/एलजीडीएस में नीचेले क्षेत्र पर बायो-टैक रखरखाव शेड का विस्तार & स्थानांतरण। अनुमानित मूल्य ₹ 2,24,36,793.00, अग्रधन ₹ 4,48,700.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 114 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: सीडब्ल्यूएस/एलजीडीएस में नीचेले क्षेत्र पर बायो-टैक रखरखाव शेड का विस्तार & स्थानांतरण। अनुमानित मूल्य ₹ 2,24,36,793.00, अग्रधन ₹ 4,48,700.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 115 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: सीडब्ल्यूएस/एलजीडीएस में नीचेले क्षेत्र पर बायो-टैक रखरखाव शेड का विस्तार & स्थानांतरण। अनुमानित मूल्य ₹ 2,24,36,793.00, अग्रधन ₹ 4,48,700.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 116 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: सीडब्ल्यूएस/एलजीडीएस में नीचेले क्षेत्र पर बायो-टैक रखरखाव शेड का विस्तार & स्थानांतरण। अनुमानित मूल्य ₹ 2,24,36,793.00, अग्रधन ₹ 4,48,700.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 117 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: सीडब्ल्यूएस/एलजीडीएस में नीचेले क्षेत्र पर बायो-टैक रखरखाव शेड का विस्तार & स्थानांतरण। अनुमानित मूल्य ₹ 2,24,36,793.00, अग्रधन ₹ 4,48,700.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 118 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: सीडब्ल्यूएस/एलजीडीएस में नीचेले क्षेत्र पर बायो-टैक रखरखाव शेड का विस्तार & स्थानांतरण। अनुमानित मूल्य ₹ 2,24,36,793.00, अग्रधन ₹ 4,48,700.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 119 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: सीडब्ल्यूएस/एलजीडीएस में नीचेले क्षेत्र पर बायो-टैक रखरखाव शेड का विस्तार & स्थानांतरण। अनुमानित मूल्य ₹ 2,24,36,793.00, अग्रधन ₹ 4,48,700.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 120 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: सीडब्ल्यूएस/एलजीडीएस में नीचेले क्षेत्र पर बायो-टैक रखरखाव शेड का विस्तार & स्थानांतरण। अनुमानित मूल्य ₹ 2,24,36,793.00, अग्रधन ₹ 4,48,700.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 121 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: सीडब्ल्यूएस/एलजीडीएस में नीचेले क्षेत्र पर बायो-टैक रखरखाव शेड का विस्तार & स्थानांतरण। अनुमानित मूल्य ₹ 2,24,36,793.00, अग्रधन ₹ 4,48,700.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 122 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: सीडब्ल्यूएस/एलजीडीएस में नीचेले क्षेत्र पर बायो-टैक रखरखाव शेड का विस्तार & स्थानांतरण। अनुमानित मूल्य ₹ 2,24,36,793.00, अग्रधन ₹ 4,48,700.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 123 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: सीडब्ल्यूएस/एलजीडीएस में नीचेले क्षेत्र पर बायो-टैक रखरखाव शेड का विस्तार & स्थानांतरण। अनुमानित मूल्य ₹ 2,24,36,793.00, अग्रधन ₹ 4,48,700.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 124 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: सीडब्ल्यूएस/एलजीडीएस में नीचेले क्षेत्र पर बायो-टैक रखरखाव शेड का विस्तार & स्थानांतरण। अनुमानित मूल्य ₹ 2,24,36,793.00, अग्रधन ₹ 4,48,700.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 125 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: सीडब्ल्यूएस/एलजीडीएस में नीचेले क्षेत्र पर बायो-टैक रखरखाव शेड का विस्तार & स्थानांतरण। अनुमानित मूल्य ₹ 2,24,36,793.00, अग्रधन ₹ 4,48,700.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 126 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: सीडब्ल्यूएस/एलजीडीएस में नीचेले क्षेत्र पर बायो-टैक रखरखाव शेड का विस्तार & स्थानांतरण। अनुमानित मूल्य ₹ 2,24,36,793.00, अग्रधन ₹ 4,48,700.00

दक्षिण मध्य रेलवे
दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, हैदराबाद
निविदा संख्या: 127 डीआरएम डब्ल्यू एचवावली 26, कार्य विवरण: एचवावली डिवीजन: सीडब्ल्यूएस/एलजीडीएस में नीचेले क्षेत्र पर बायो-टैक रखरखाव शेड का विस्तार & स्थानांतरण। अनुमानित मूल्य ₹ 2,24,36,793.00, अग्रधन ₹ 4,48,700.00

निविदा सं.टीएम-केओएलएएससी-26-28
निम्न निविदा सूचना को ई-प्रोक्वायर्मेंट द्वारा दर्शाया गया है।

निविदा सं.टीएम-केओएलएएससी-26-28
निम्न निविदा सूचना को ई-प्रोक्वायर्मेंट द्वारा दर्शाया गया है।

निविदा सं.टीएम-केओएलएएससी-26-28
निम्न निविदा सूचना को ई-प्रोक्वायर्मेंट द्वारा दर्शाया गया है।

निविदा सं.टीएम-केओएलएएससी-26-28
निम्न निविदा सूचना को ई-प्रोक्वायर्मेंट द्वारा दर्शाया गया है।

निविदा सं.टीएम-केओएलएएससी-26-28
निम्न निविदा सूचना को ई-प्रोक्वायर्मेंट द्वारा दर्शाया गया है।

निविदा सं.टीएम-केओएलएएससी-26-28
निम्न निविदा सूचना को ई-प्रोक्वायर्मेंट द्वारा दर्शाया गया है।

निविदा सं.टीएम-केओएलएएससी-26-28
निम्न निविदा सूचना को ई-प्रोक्वायर्मेंट द्वारा दर्शाया गया है।

निविदा सं.टीएम-केओएलएएससी-26-28
निम्न निविदा सूचना को ई-प्रोक्वायर्मेंट द्वारा दर्शाया गया है।

निविदा सं.टीएम-केओएलएएससी-26-28
निम्न निविदा सूचना को ई-प्रोक्वायर्मेंट द्वारा दर्शाया गया है।

निविदा सं.टीएम-केओएलएएससी-26-28
निम्न निविदा सूचना को ई-प्रोक्वायर्मेंट द्वारा दर्शाया गया है

